@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

सांगठनिक विस्तार के लिए 120 दिनों के राष्ट्रव्यापी विस्तृत प्रवास कार्यक्रम का शुभारंभ

वर्ष-15, अंक-24 16-31 दिसम्बर, 2020 (पाक्षिक) ₹20

'हमारे लिए विरासत का अर्थ है हमारी संस्कृति, हमारा विश्वास, हमारे मूल्य'

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संविधान दिवस कार्यक्रम पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

हरिद्वार (हर की पौड़ी, गंगा घाट) में 'गंगा आरती' करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर नई दिल्ली स्थित श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 गुरु नानक देव जी समाज और व्यवस्था में सुधारों के बहुत बड़े प्रतीकः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि यह काशी के लिए एक और विशेष अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि माता...

09 हमारा हर कदम नागरिकों के उत्थान और राज्य एवं देश के विकास के प्रति...

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 05 दिसंबर, 2020 को...

14 किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जायेगी और न ही बंधक होगीः रविशंकर प्रसाद ...

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 7 दिसंबर...

20 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में चार सीटें हासिल...

26 कोरोना संकट के समय भी देश की विकास यात्रा नहीं थमीः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 30 नवंबर को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के...

वैचारिकी

संगठन का आधार / दीनदयाल उपाध्याय 22

श्रद्धांजलि

संगठन शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे 24

नहीं रहीं वरिष्ठ भाजपा नेता किरण माहेश्वरी 24

अन्य

भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में सेतु का काम करना चाहिएः जगत प्रकाश नड्डा 12

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में तेजी 17

सुरक्षित व सस्ते टीके के विकास हेतु दुनिया की नजर भारत की तरफ 25

इन्वेस्ट इंडिया ने 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता 27

रि-लर्निंग, रि-थिंकिंग, रि-इनोवेटिंग और रि-इंवेंटिंग, कोविड-19 के बाद की व्यवस्था होगीः नरेन्द्र मोदी 28

रेल विद्युतीकरण कार्य में जोरदार वृद्धि 29

भारत ने मलेरिया के मामलों को कम करने में हासिल की प्रभावी सफलताः विश्व स्वास्थ्य संगठन 30

स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 9 लाख परामर्श का पूरा किया आंकड़ा 31

मन की बात 32

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का इतिहास है। जिन्होंने छल किया, उनके लिए झूठ फैलाना मजबूरी बन चुकी है। लेकिन अब छल से नहीं, गंगाजल जैसी पवित्र नीयत से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा।

जगत प्रकाश नड्डा

जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटा था तो उस समय तक जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन एक्ट लागू नहीं था, दलितों को वहां आरक्षण नहीं मिलता था, आदिवासी लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं थे, पाकिस्तान से आये हुए लोग जो भारत में बसे थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब उनको आजादी मिली है।

अमित शाह

गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में सिंधू भवन क्रॉस रोड और साणद जंक्शन पर बनाए गए फ्लाईओवर्स का लोकार्पण किया। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संकट के समय भी देश की विकास यात्रा थमी नहीं है। मैं समय से पूर्व इन योजनाओं को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

राजनाथ सिंह

सशस्त्र सेना के झंडा दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और सेवा को सलाम करता हूं। यह दिन देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमारे गंभीर दायित्व की याद हमें दिलाता है।

बी. एल. संतोष

एनसीपी के काका, डीएमके के स्टालिन, आप के एके, कैप्टन अमरिंदर सिंह... दोहरी बातें करने वाले, यू टर्न में माहिर, कपट से भरे हैं। अब चुनाव-दर-चुनाव स्पष्टीकरण देते हुए उनकी पोल खुल गयी है। अपनी अराजकता के लिए आपको आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना होगा। #FarmersWithPmModi

थावरचंद गहलोत

जरा सोचिए...अगर सरकार की मंशा मंडियों को खत्म करने की होती, तो पिछले 6 वर्षों में मंडियों का डिजिटलीकरण क्यों किया जाता? ई-नाम के नाम से चल रहे डिजिटल प्लेटफार्म पर अब तक देश भर की 1,000 मंडियां पंजीकृत हैं।

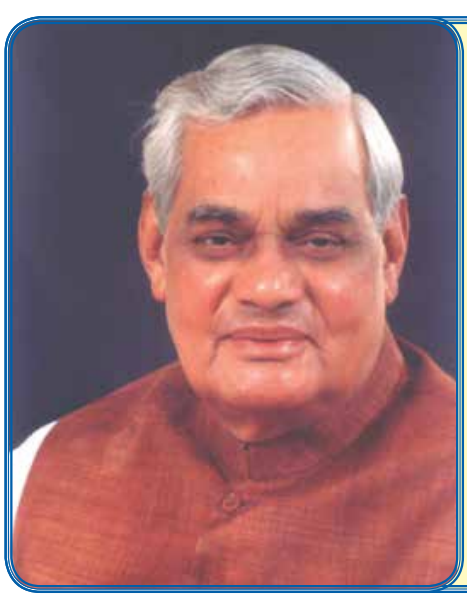

'कमल संदेश' परिवार

की ओर से

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी

को उनकी जयंती (25 दिसंबर) पर भावभीनी श्रद्धांजलि!

शत शत नमन!

कृषि सुधारों से कृषि क्षेत्र का होगा कायाकल्प

आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में पूरा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है जिससे आम जन-जीवन में भारी सुधार हो रहा है। जहां एक ओर हाल में हुए कृषि सुधारों का पूरे देश में स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाए गए भ्रम के कारण किसान समुदाय का एक वर्ग कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जता रहा है। अब जबकि सरकार इन आपत्तियों पर खुले मन से विचार कर रही है तो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया का राजनीतिकरण कर संवाद को तर्कहीन मांगों को उठाकर बाधित किया जा सके। ध्यान देने योग्य है कि जब भी असंगत मांगों पर अड़ियल रूख अपनाया गया है, जनता ने कभी ऐसे रवैये को समर्थन नहीं दिया है।

कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020; कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 ऐसे तीन कानून है, जिसकी मांग कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए इस क्षेत्र के हितधारकों द्वारा कई वर्षों से उठाए जा रहे थे। इन सुधारों के लिए देशभर में विभिन्न मांगों पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी तथा अनेक किसान नेता, कृषि विशेषज्ञ व विभिन्न राजनैतिक दल इसकी मांग कर रहे थे। इन सुधारों से किसान दशकों के बंधनों से मुक्त हो गए हैं और अब अपनी उपज अपने पसंद के किसी भी खरीददार को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इतना ही नहीं, किसान अब देश के किसी भी भाग में अपनी उपज बेच सकता है। इन कानूनों ने न केवल किसानों को स्वतंत्र किया है, बल्कि स्पर्धात्मक बाजार भी उपलब्ध कराया है जिससे उन्हें अपनी उपज का अधिकतम दाम मिल सकेगा। साथ ही, कृषि क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक, बेहतर बाजार व्यवस्था एवं खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। किसान अब व्यापार एवं निर्यात की गतिविधियों से सीधा जुड़ पाएगा। इन सुधारों का लाभ किसानों को तत्काल तो मिलेगा ही, साथ ही आने वाले समय में उनका सशक्तिकरण भी होगा और कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत अंग बनकर उभरेगा।

मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने, कृषि के आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कृत-संकल्पित है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान व्यवस्था में जमे निहित स्वार्थी तत्व भ्रम का वातावरण बना किसानों को आधारहीन आशंकाओं से दिग्भ्रमित कर सुधारों का मार्ग अवरूद्ध करना चाहते हैं

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि मोदी सरकार ऐसी सरकार है, जिसने पहली बार किसान हितैषी, ग्रामीण जीवन केंद्रित एवं कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कृषि लागत का डेढ़ गुना तय किया है। इतनी ही नहीं, पिछले छह वर्षों में एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की है। नए फसलों को इसके दायरे में लाया है और लगातार रिकार्ड खरीदारी की हैं। देश के इतिहास में पहली बार नीम-कोटेड यूरिया के माध्यम से खाद में कालाबाजारी खत्म कर किसानों को आसानी से खाद-बीज उपलब्ध कराया गया है और इनके लिए लंबी-लंबी लाइनें खत्म की हैं। मोदी सरकार द्वारा लाई गई व्यापक फसल बीमा योजना से अब फसल को लेकर हर किसान की चिंताएं खत्म हुई हैं और सुरक्षा का मजबूत भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ है। पीएम-किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के इतिहास में पहली बार किसानों के खाते में अब तक एक लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इनके अलावा मत्स्य पालन, बागवानी एवं दूग्ध उत्पादन जैसे अन्य कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र एवं किसानों के लिए किए गए कार्यों को यदि विस्तार से बताया जाए तो कई खंड लिखने पड़ेंगे।

मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने, कृषि के आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कृत-संकल्पित है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान व्यवस्था में जमे निहित स्वार्थी तत्व भ्रम का वातावरण बना किसानों को आधारहीन आशंकाओं से दिग्भ्रमित कर सुधारों का मार्ग अवरूद्ध करना चाहते हैं। सरकार द्वारा इन भ्रम, चिंताओं एवं आशंकाओं को निर्मूल प्रमाणित करने के प्रयासों से देश के बड़े भू-भाग में किसान इन सुधारों की आवश्यकताओं समझ रहे हैं और इन कानूनों का खुले दिल से समर्थन भी कर रहे हैं। आज जब पूरा देश हर क्षेत्र में सुधारों का भारी समर्थन कर रहा है, इन कृषि सुधारों से 21वीं सदी के 'आत्मनिर्भर भारत' का मार्ग निश्चय ही प्रशस्त होगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

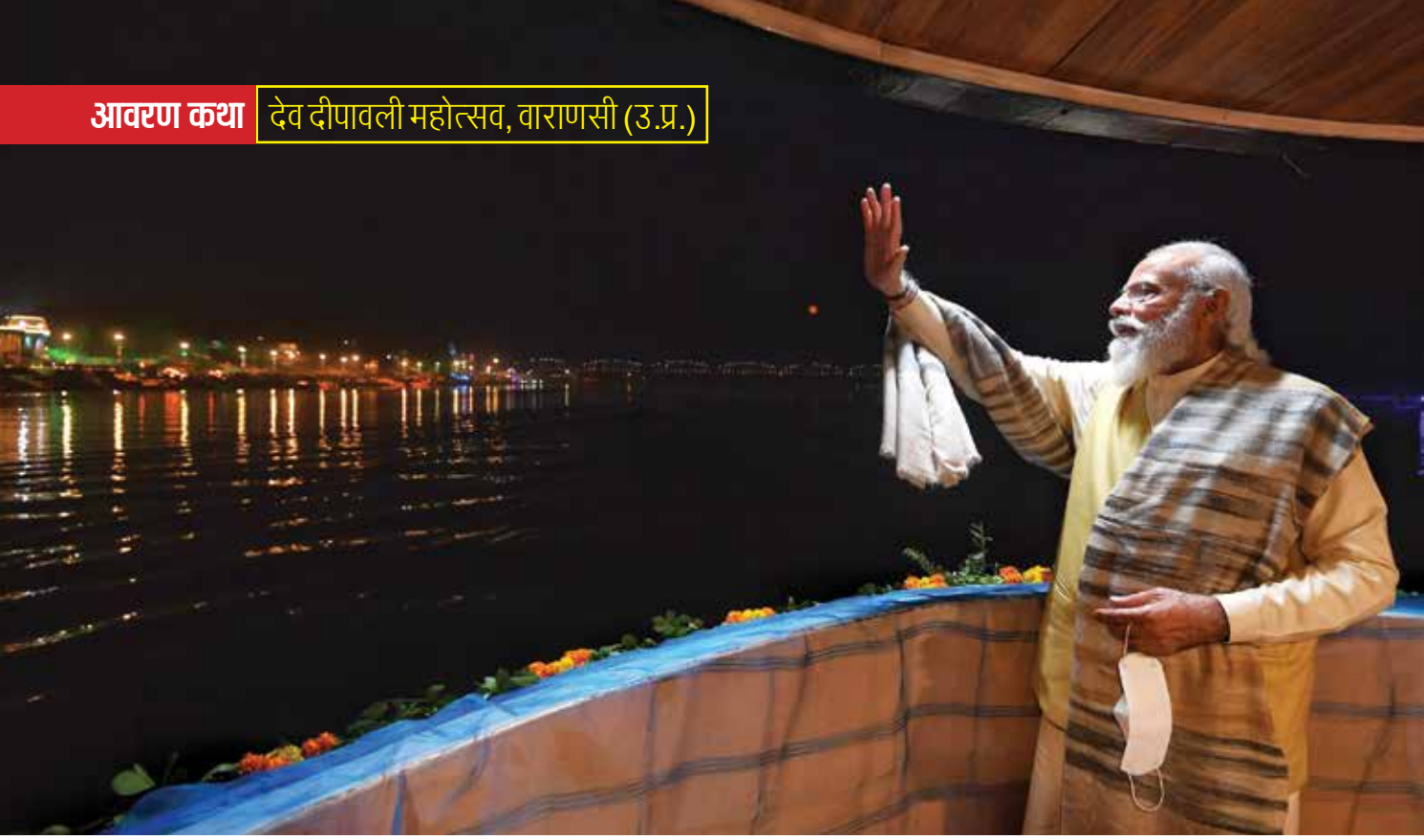

गुरु नानक देव जी समाज और व्यवस्था में सुधारों के बहुत बड़े प्रतीक: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने प्राचीन शहर की महिमा का वर्णन किया और कहा कि काशी ने युगों-युगों से दुनिया का मार्गदर्शन किया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि यह काशी के लिए एक और विशेष अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जो 100 साल से अधिक पहले काशी से चुराई गई थी, अब फिर से वापस आ रही है। यह काशी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे देवी-देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के साथ-साथ हमारी अमूल्य धरोहर हैं।

उन्होंने ने कहा कि अगर ऐसा प्रयास पहले किया गया होता, तो देश को ऐसी कई प्रतिमाएं मिल जातीं। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए विरासत का मतलब देश की विरासत है, जबकि कुछ लोगों के लिए

इसका मतलब है उनका परिवार और उनके परिवार का नाम। उन्होंने कहा कि हमारे लिए विरासत का अर्थ है हमारी संस्कृति, हमारा विश्वास, हमारे मूल्य, जबकि दूसरों के लिए इसका मतलब हो सकता है उनकी मूर्तियां और उनकी पारिवारिक तस्वीरें।

श्री मोदी ने गुरु नानक देव जी को समाज और व्यवस्था में सुधारों का बहुत बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जब भी समाज और राष्ट्र हित में बदलाव होते हैं, तो विरोध के लिए अकारण आवाज उठती है। लेकिन जब उन सुधारों का महत्व स्पष्ट हो जाता है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। उन्होंने इसे गुरु नानक देवजी के जीवन से प्राप्त पाठ के रूप में उद्धृत किया।

उन्होंने कहा कि जब काशी के लिए विकास कार्य शुरू हुए तो प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब

काशी ने तय किया था कि विश्वनाथ कॉरिडोर बाबा के दरबार तक बनाया जाएगा, तो प्रदर्शनकारियों ने उसकी भी आलोचना की थी, लेकिन आज बाबा की कृपा से काशी का गौरव फिर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार और मां गंगा के बीच सदियों से सीधा संबंध फिर से स्थापित हो रहा है।

श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से उन्हें काशी में प्रकाशोत्सव में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने प्राचीन शहर की महिमा का वर्णन किया और कहा कि काशी ने युगों-युगों से दुनिया का मार्गदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना प्रतिबंधों के कारण वह शहर में नहीं आ सके, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। श्री मोदी ने कहा कि बहुत बार और उत्सुकता से इसके द्वारा बनाए गए शून्य को उन्होंने महसूस किया। श्री मोदी कहा कि वे इस दौरान अपने लोगों से कभी दूर नहीं रहे और महामारी के समय व्यवस्थाओं पर नजर रखते थे। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान काशी के लोगों द्वारा प्रदर्शित सार्वजनिक सेवा की भावना की प्रशंसा भी की। ■

एनएच-19 पर वाराणसी-प्रयागराज खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना का उद्घाटन

'भारत के कृषि उत्पाद समूचे विश्व में प्रसिद्ध हैं'

आधुनिकतम संपर्क व्यवस्था का विस्तार होगा तो किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के वाराणसी-प्रयागराज खंड के 6 लेन चौड़ीकरण की परियोजना का वाराणसी में उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि काशी में कनेक्टिविटी बेहतर करने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए बीते समय में किए गए प्रयासों के परिणाम आज देख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वाराणसी में यातायात जाम की समस्या को कम करने के लिए नए राजमार्ग, फ्लाईओवर और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए व्यापक काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकतम संपर्क व्यवस्था का विस्तार होगा तो हमारे किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में शीतगृह और गांव में आधुनिक शैली की सड़कों को विकसित करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इन कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि का आवंटन किया गया है।

उन्होंने एक उदाहरण देकर यह समझाया कि किस तरह से सरकार के प्रयासों और आधुनिक बुनियादी ढांचे से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास के क्रम में 2 वर्ष पहले चंदौली में काले चावल की शुरुआत की गई और पिछले वर्ष एक किसान समिति का गठन किया गया और लगभग 400 किसानों को खरीफ सीजन में बुवाई के लिए चावल के यह बीज दिए गए। जहां सामान्य चावल 35 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, वहीं काला चावल प्रति किलोग्राम 300 रुपये तक में बेचा गया। पहली बार इन चावलों का ऑस्ट्रेलिया में निर्यात किया गया, वह भी लगभग 800 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर।

> • **नए कृषि सुधार, किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं और साथ ही साथ पुरानी व्यवस्था को भी जारी रखा जाएगा यदि कोई उस व्यवस्था को अपनाना चाहता है तो अपना सकता है**

उन्होंने कहा कि भारत के कृषि उत्पाद समूचे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि क्यों किसानों को ऐसे बड़े बाजार और ऐसी ऊंची कीमतों तक पहुंच से वंचित किया जाए। श्री मोदी ने कहा कि नए कृषि सुधार, किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं और साथ ही साथ पुरानी व्यवस्था को भी जारी रखा जाएगा यदि कोई उस व्यवस्था को अपनाना चाहता है तो अपना सकता है।

उन्होंने कहा कि पहले मंडियों के बाहर गैर-कानूनी ढंग से लेन-देन किए जाते थे, लेकिन अब छोटे किसान भी इस गैर कानूनी खरीद-फरोख्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठा सकते हैं।

परंपरागत रूप से जारी एमएसपी व्यवस्था की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी में हर बार मामूली वृद्धि की जाती है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बहुत कम होती है। यह परंपरा सालों से बनी हुई थी। किसानों के नाम पर कर्ज माफी के बड़े-बड़े पैकेज की घोषणा की जाती थी लेकिन यह छूट, यह राहत छोटे और सीमांत किसानों तक नहीं पहुंच पाती थी।

उन्होंने कहा कि जब आप इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने का वादा किया था और उसे करके दिखाया, किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लागत से डेढ़ गुना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा किया था, उसे पूरा कर दिखाया। यह वादे सिर्फ कागजों में पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि किसानों के बैंक खातों में पहुंचे हैं।

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 5 वर्षों में किसानों से 6.5 करोड़ रुपये की दलहन की खरीद की गई थी। जबकि उसके बाद के 5 वर्षों में 49000 करोड़ों रुपये की दाल की खरीद किसानों से की गई जो कि लगभग 75 गुना ज्यादा है। 2014 से पहले के 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये की धान की खरीद की गई, जबकि उसके बाद के 5 वर्षों में हमने 5 लाख करोड़ रुपये की धान की खरीद किसानों से एमएसपी पर की, जो कि लगभग ढाई गुना ज्यादा है और यह पैसा किसानों के पास पहुंचा है।

श्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के 5 वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा गया, जबकि उसके बाद के 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये की गेहूं की खरीद की गई, जो 2 गुना ज्यादा है। उन्होंने पूछा कि सरकार का इरादा अगर एमएसपी और मंडी व्यवस्था को खत्म करने का था, तो सरकार इतना अधिक खर्च क्यों करती। उन्होंने जोर दिया कि सरकार मंडियों के आधुनिकीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।

• 2014 से पहले के 5 वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा गया, जबकि उसके बाद के 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये की गेहूं की खरीद की गई, जो 2 गुना ज्यादा है

विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह वही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि पर सवाल उठाते हैं और यही यह अफवाह फैलाते हैं कि यह पैसा चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है और चुनाव के बाद यही पैसा ब्याज समेत वापस ले लिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि एक राज्य में विपक्ष की सरकार है और उसके राजनीतिक स्वार्थों के कारण किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सहायता देश के 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सीधे बैंक खातों में जमा करवा कर दी जा रही है। अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपये किसानों के पास पहुंचे हैं।

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन किसानों को नए कृषि सुधारों को लेकर जरा भी संदेह आज है वह भविष्य में इन्हीं कृषि सुधारों के चलते लाभान्वित होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। ■

हमारा हर कदम नागरिकों के उत्थान और राज्य एवं देश के विकास के प्रति समर्पित है: जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले छह वर्षों में जितनी भी योजनाओं की शुरुआत की है, वे सभी समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए ही है चाहे उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उजाला योजना हो या सौभाग्य योजना

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 05 दिसंबर, 2020 को आईआरडीटी ऑडिटोरियम, देहरादून में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को संबोधित किया और उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चल रही विकास यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए इससे जुड़ने का आह्वान किया। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी डॉ. संजय मयूख के साथ-साथ प्रदेश के कई मंत्री एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवियों ने इस परिचर्चा में भाग लिया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विगत छह वर्षों से चल रही विकास यात्रा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ज्ञात हो कि श्री नड्डा ने 120 दिनों के अपने राष्ट्रव्यापी विस्तृत प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत चार दिवसीय उत्तराखंड प्रवास से की है।

श्री नड्डा ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का देश में अपना एक प्रमुख स्थान है चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या देश के सुरक्षा की बात ही क्यों न हो, उत्तराखंड ने हमेशा आगे बढ़कर देश का नेतृत्व किया है। उत्तराखंड ने देश को सैन्य नेतृत्व प्रदान किया है चाहे वह चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ हों, फील्ड मार्शल हों, जनरल्स हों या फिर सीमा की सुरक्षा में अपने जानों की बाजी लगाने वाले वीर जवान हों। ब्यूरोक्रेसी, रिसर्च और विज्ञान में तरक्की की दृष्टि से भी उत्तराखंड ने देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया है। मैं ऐसी महान देवभूमि उत्तराखंड की धरती को नमन करता हूं।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के सहयोग से देश को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर और कृतसंकल्पित है लेकिन भ्रष्टाचार, गुंडाराज और देश के खिलाफ काम करने वाले लोग एकजुट होकर देश के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में हमने 110 विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 74 सीटों पर विजय

- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के सहयोग से देश को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर और कृत संकल्पित है**

श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर अपनी मुहर लगाईं। उन्होंने कहा कि समग्र राष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व को इसलिए अपना भरपूर आशीर्वाद दे रही है क्योंकि उन्होंने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलते हुए इसे विकास आधारित बनाया है। उन्होंने विकासवाद का नारा दिया है तथा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को अपना मूलमंत्र बनाया है। भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर चलते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड के खिलाफ देश को साथ लेकर लड़ाई लड़ी है। दुनिया के बड़े-बड़े देश अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बावजूद अपने आपको जहां असहाय पा रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समय पर साहसिक निर्णय लेते हुए न केवल देश को सुरक्षित किया, बल्कि इससे लड़ने के लिए भी देश को एकजुट किया। आज हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी 15 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पर्याप्त संख्या में आज डेडिकेटेड कोविड बेड्स हैं, आज वेंटीलेटर उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और पीपीई किट्स का तो हम आज निर्यात कर रहे हैं। उत्तराखंड भी इस मामले में पीछे नहीं है। आज उत्तराखंड में 13 हजार से अधिक टेस्टिंग प्रतिदिन हो रहे हैं तो लगभग 58 लैब्स भी बनाए गए हैं। राज्य में 11 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बने हैं तो पर्याप्त संख्या में आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर सपोर्ट वाले डेडिकेटेड बेड्स भी उपलब्ध हैं। श्री नड्डा ने न केवल स्वास्थ्य के मुद्दे को एड्रेस किया, बल्कि आर्थिक मुद्दे को भी गंभीरता से लेते हुए गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान और गरीब कल्याण रोजगार योजना जैसे इनिशिएटिव की शुरुआत की। गरीब कल्याण पैकेज के तहत लगभग 8 करोड़ परिवारों को तीन गैस सिलिंडर मुफ्त उपलब्ध कराये गए, तो 20 करोड़ महिला जन-धन खाता धारकों के एकाउंट में 500-500 रुपये की तीन किस्तें डाली गईं। दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्गों को लॉकडाउन के दौरान 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दो किस्तें दी गईं। एक लाख करोड़ रुपये कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से रखे गए। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कोविड मैनेजमेंट के प्रयासों को सराहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था

- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकासवाद का नारा दिया है तथा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को अपना मूलमंत्र बनाया है। भाजपा इसी आधार पर चलते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है**

- **दुनिया के बड़े-बड़े देश अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बावजूद अपने आपको जहां असहाय पा रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समय पर साहसिक निर्णय लेते हुए न केवल देश को सुरक्षित किया, बल्कि इससे लड़ने के लिए भी देश को एकजुट किया**

प्राप्त की। हमारी जीत का स्ट्राइक रेट 67 प्रतिशत रहा। बिहार की जनता ने विपक्ष के गुंडाराज और अराजकता की राजनीति को नकारते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकासवाद की राजनीति में अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त की। बिहार में हमारी लड़ाई एक ऐसे अपवित्र गठबंधन से थी जिसमें एक बिहार की धरती को नरसंहार से लहुलूहान करने वाली माले थी, तो दूसरी थी गुंडाराज का प्रतीक राजद और तीसरी थी कांग्रेस जिसने देश के विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। राहुल गांधी, पी चिदंबरम, शशि थरूर सहित पूरी कांग्रेस ने धारा 370 के ख़त्म होने का विरोध किया। पाकिस्तान ने राहुल गांधी के इस बयान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में किया, लेकिन ऐसे अपवित्र गठबंधन के बावजूद बिहार की जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत देकर यह बता दिया कि वह विकास पथ पर अग्रसर होना चाहती है।

श्री नड्डा ने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव के साथ-साथ देश के कई राज्यों में उपचुनाव भी थे। गुजरात में भाजपा को आठ की आठ सीटों पर तो मध्य प्रदेश में 28 में 19 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 7 में 6 सीटों पर, कर्नाटक की दो की दो सीटों पर और मणिपुर में चार सीटों पर भाजपा को विजय मिली। तेलंगाना में एक सीट पर उप-चुनाव था जो टीआरएस के एक परिवार के वर्चस्व में थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली। मणिपुर से लेकर गुजरात तक और कर्नाटक, तेलंगाना से लेकर लद्दाख तक देश की जनता ने भाजपा में विश्वास व्यक्त किया और प्रधानमंत्री

की गई जिसमें से कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये और एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का अभियान शुरू किया है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले छह वर्षों में जितनी भी योजनाओं की शुरुआत की है, वे सभी समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए ही है चाहे उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उजाला योजना हो या सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हुए 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये सालाना का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया।

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष पर कुछ अधिक बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तराखंड और देश की जनता उनकी नकारात्मक राजनीति और विकास में रोड़े अटकाने की नीति से भलीभांति परिचित है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज देश में लगभग कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रह गई है जो पारिवारिक पार्टी न बन गई हो। बाकी दलों के लिए परिवार ही पार्टी है जबकि भाजपा के लिए पार्टी ही परिवार है। पार्टियों का पारिवारिक बन जाना प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की विचारधारा के बल पर आगे बढ़ते हुए देश का विकास करना और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना ही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के उन्मूलन पर बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति के बल पर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को धाराशायी किया गया तो जम्मू-कश्मीर में रोशनी आई और रोशनी स्कैंडल का भी पता चला।

- **आज हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी 15 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है**
- **गरीब कल्याण पैकेज के तहत लगभग 8 करोड़ परिवारों को तीन गैस सिलिंडर मुफ्त उपलब्ध कराये गए, तो 20 करोड़ महिला जन-धन खाता धारकों के एकाउंट में 500-500 रुपये की तीन किस्तें डाली गईं**
- **दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्गों को लॉकडाउन के दौरान 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई**
- **'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था की गई जिसमें से कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये और एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए**

पहले जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन एक्ट लागू नहीं था लेकिन अब जब देश के बाकी कानून भी यहां लागू हुए हैं तो एक-एक करके घपले-घोटाले बाहर आते जा रहे हैं कि किस तरह पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस ने यहां के गरीबों का हक मारते हुए लूट मचाई थी। आज पता चल रहा है कि गरीबों के लिए आवंटित होने वाली जमीन को भी इन लोगों ने अपने नाम पर कर लिया और पता नहीं कितने घोटाले किये होंगे। गुपकार समझौता देश हित में नहीं, इसमें शामिल लोगों के भ्रष्टाचार को, इनके अस्तित्व को बचाने का समझौता है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भ्रष्टाचार मुक्त, निर्णायक और सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। विगत छह वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई कहानी लिखी है, विदेश नीति और रक्षा नीति सुदृढ़ हुई है और पूरे विश्व में भारत और हर भारतवासी का मान-सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने यूएन के मंच पर खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत की बात कर उसे आईना दिखाया। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता, देश की जनता इसी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य की श्री त्रिवेंद्र सिंह सरकार पर भी भरोसा बनाए रखेगी। हमारा हर कदम नागरिकों के उत्थान और राज्य एवं देश के विकास के प्रति समर्पित है। ■

भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में सेतु का काम करना चाहिए: जगत प्रकाश नड्डा

राजनीति एक मिशन है और हम सब देश में विकास रूपी परिवर्तन लाने के लिए एक उपकरण हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है कि भले हमें शाबासी मिले न मिले, हम देश के उत्थान में लगातार काम करते रहें

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 06 दिसंबर 2020 को प्रदेश भाजपा कार्यालय, देहरादून में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से एजेंडे में सेट होने के बजाय एजेंडा सेट करने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत, राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा एवं राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश के साथ-साथ कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में राज्य के कोने कोने से बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ता इस उद्बोधन को सुनने के लिए वर्चुअली जुड़े। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सभागार में उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि 120 दिनों के राष्ट्रव्यापी प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत श्री नड्डा ने उत्तराखंड से की है। उत्तराखंड प्रवास का उनका तीसरा दिन था।

श्री नड्डा ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमने 110 विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 74 सीटों पर विजय प्राप्त की। हमारी जीत का स्ट्राइक रेट 67 प्रतिशत रहा। बिहार की जनता ने विपक्ष के गुंडाराज और अराजकता की राजनीति को नकारते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकासवाद की राजनीति में अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त की। बिहार में जंगलराज वाली राजद, भ्रष्टाचार की पर्यायवाची कांग्रेस और नरसंहार और हिंसा में विश्वास रखने वाली माले का गठबंधन था लेकिन बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश देकर यह दिखा दिया कि वो विकासवाद की राजनीतिक संस्कृति के साथ चलना चाहती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सारे दल लामबंद हो गए थे लेकिन वहां की जनता ने भी विकास की राह चुनी। इतना ही नहीं, बिहार से लेकर मणिपुर तक और तेलंगाना से लेकर गुजरात तक हुए विधान सभा चुनाव और उप-चुनावों में देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपना आशीर्वाद देकर यह निर्णय दे दिया कि अब देश में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति का अंत हो चुका है।

कोविड मैनेजमेंट पर बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सही समय पर सही और साहसिक निर्णय लेते हुए न केवल 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के हर वर्ग को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने की मुहिम की भी शुरुआत की। चाहे प्रतिदिन टेस्टिंग की संख्या हो, टेस्टिंग लैब्स हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, वेंटिलेटर का उत्पादन हो, पीपीई किट का उत्पादन हो, फेस कवर का निर्माण हो, हर सेक्टर में भारत ने लॉकडाउन के दौरान

उल्लेखनीय प्रगति की।

श्री नड्डा ने कहा कि किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि के तहत अब तक एक लाख करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। अब केंद्र सरकार 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' का क्रियान्वयन कर रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को कहीं भी राशन आसानी से उपलब्ध हो सके। देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीनों तक के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति की गई, इतने बड़े पैमाने पर शुरू किया गया अपने-आप में यह अनोखा अभियान था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था की गई जिसमें से कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये और एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। चुनाव के दौरान हमें हर विज्ञापन में कुमाऊं रीजन की रंगोली का इस्तेमाल किया, हम इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि जब सारी राजनीतिक पार्टियों ने खुद को लॉकडाउन कर लिया था तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने खुद को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हर जरूरतमंद की सेवा की। उन तक फूड पैकेट्स पहुंचाए, राशन किट्स पहुंचाए, बुजुर्गों तक दवाइयां पहुंचाई, फेस कवर और सेनिटाइजर का वितरण किया गया। सैकड़ों जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, अस्पतालों में फल पहुंचाए गए, बच्चों को फल और किताबें उपलब्ध कराई गई और कई अन्य तरह की सहायता भी पहुंचाई गई।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश

के गांव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए हमने आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी इतनी जनोपयोगी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है कि हमें किसी के एजेंडे में सेट होने के बजाय अपनी पार्टी और सरकार का एजेंडा खुद सेट करना चाहिए। आजादी के 70 सालों में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन न तो महिलाओं के पास टॉयलेट्स थे, न गरीबों की बैंकों तक पहुंच थी, न हर गांव में बिजली थी और न ही गरीबों के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा थी लेकिन केवल 6 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल में हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंची है, महिलाओं को इज्जत घर मिले हैं, गरीबों की बैंकों तक पहुंच हुई है और उनके मुफ्त इलाज की भी व्यवस्था हुई है। उत्तराखंड में 5.22 लाख टॉयलेट्स बने, यह ओडीएफ घोषित हुआ, घरों तक बिजली पहुंची और आयुष्मान भारत में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एक और आयाम जोड़ते हुए अटल आयुष्मान भारत की संरचना की, जिसके तहत अब तक राज्य के लगभग 2.12 लाख लोगों को लाभ पहुंचा है और इसमें सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है। पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना में सवा करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इस पर लगभग 15,500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। राज्य में 12 हजार करोड़ रुपये की लगत से चार धाम की यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को शुरू किया गया है और नमामि गंगा योजना के तहत राज्य के हर भाग में करोड़ों रुपये की परियोजना से मां गंगा को निर्मल बनाने पर द्रुत गति से कार्य हो रहा है। प्रदेश में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सेन्ट्रल इंस्टीटयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनयरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और कोस्ट गार्ड से जुड़े हुए संस्थान जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान खुले हैं। राज्य में 50 हजार के लगभग वाटर कनेक्शन दिए गए हैं जिससे घरों तक जल की पहुंच सुनिश्चित हुई है।

श्री नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड की बात हो या हिमाचल प्रदेश की, यहां के लगभग हर घर से देश के जवान निकले हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा में लगातार डटे रहते हैं। यह मोदी सरकार है जिसने 40 वर्षों से लंबित वन रैंक, वन पेंशन की मांग को पूरा किया। अकेले उत्तराखंड में लगभग एक लाख सैन्य कर्मचारियों को इसका लाभ हुआ है। आज हम न केवल विश्वस्तरीय बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं, बल्कि इसका हम निर्यात भी कर रहे हैं। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए 36 राफेल आ रहे हैं, 28 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरर्स के साथ साथ सर्फेस टू एयर मिसाइल और होवित्जर तोपों का बेड़ा भी शामिल हुआ है।

उन्होंने कहा कि आज बॉर्डर पर हंगामा इसलिए मचा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हमने बॉर्डर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नया इतिहास लिखा है और सीमा पर जवान मुस्तैद हैं। सीमा पर सड़कें बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, रनवे बन रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल राष्ट्र को समर्पित किया है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दुश्मनों को उसके घर में मात दी है और आतंकियों का सफाया किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर तरीके से तैयार है।

श्री नड्डा ने कहा कि एक बहुत बड़ा कालखंड घिस गया, लेकिन कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण धारा 370 नहीं घिस पाया जिसके बारे में पंडित नेहरू ने कहा था। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह की कुशल रणनीति थी जिसके बल पर हमने धारा 370 को धाराशायी किया। राहुल गांधी से लेकर चिदंबरम, शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर तक तमाम कांग्रेस नेता आज धारा 370 को फिर से लागू करने की वकालत कर रहे हैं, ये लोग राजनीति में इस स्तर तक गिर चुके हैं कि वे अब देश के विरोध में खड़े नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान इनके बयानों का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ करता है, ये लोग दुश्मनों के देश में मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। भगवान् इन्हें सद्बुद्धि दें!

• बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां परिवार की पार्टी बन चुकी है, यह केवल भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है, राष्ट्र का विकास ही उसका सिद्धांत है और अंत्योदय एवं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही उसका मूल मंत्र

श्री नड्डा ने कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर में धारा 370 लागू था, तब तक वहां एंटी करप्शन लॉ लागू नहीं थे। देश के बाकी कानून भी वहां लागू नहीं होते थे। आज जब धारा 370 के समाप्त होने से जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन लॉ लागू हुआ है तो एक-एक करके हर भ्रष्टाचार पर रोशनी पड़ रही है और रोशनी स्कैंडल भी सामने आ रहा है। गुपकार एलायंस ऐसे ही भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। वे अपने द्वारा किये गए भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ऐसे एलायंस कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार में एक भी गुनाहगार नहीं बचेगा लेकिन हां, यह याद जरूर रखना चाहिए कि हम राजनीतिक विद्वेष से कोई काम नहीं करते। कानून अपना काम करेगा।

श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में सेतु का काम करना चाहिए। हमने हर क्षेत्र में विकास को नया आयाम दिया है। राजनीति एक मिशन है और हम सब देश में विकास रूपी परिवर्तन लाने के लिए एक उपकरण हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है कि भले हमें शाबासी मिले न मिले, हम देश के उत्थान में लगातार काम करते रहें। बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां परिवार की पार्टी बन चुकी है, यह केवल भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है, राष्ट्र का विकास ही उसका सिद्धांत है और अंत्योदय एवं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही उसका मूल मंत्र। ■

किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जायेगी और न ही बंधक होगी: रविशंकर प्रसाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के प्रति सदैव समर्पित है। केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों के माध्यम से किसानों के लिए नये-नये अवसर तलाश कर उन्हें उपलब्ध कराना चाहती है, ताकि किसान सशक्त बनें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलें

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 7 दिसंबर, 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस-वार्ता को संबोधित किया और कृषि सुधारों पर दोहरा रवैया अपनाकर जनता को गुमराह करने की विपक्ष की साजिश पर जमकर हमला बोला।

श्री प्रसाद ने कहा कि किसानों के हित में कृषि सुधारों से संबंधित जो कानून बने हैं, उस पर कुछ किसान संगठनों की कुछ चिंताएं हैं जिस पर सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता चल रही है, लेकिन इस बीच अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए निहित स्वार्थों के कारण कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल किसानों की मांग की आड़ में उन्हें गुमराह करते हुए अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने लगे हैं। यह ऐसी पार्टियों के शर्मनाक चेहरे और दोहरे रवैये को उजागर करता है।

श्री प्रसाद ने कहा कि कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगें पूरी हुई हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुये हैं, बल्कि उन्हें नये अधिकार भी मिले हैं, नये अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है लेकिन कृषि सुधारों की बात करने वाली विपक्षी पार्टियां केवल सरकार का विरोध करने के नाम पर किसानों के हित के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कांग्रेस 10 वर्षों के यूपीए सरकार के दौरान न केवल इन्हीं सुधारों की बात कर रही थी, बल्कि अपने शासित राज्यों में वह बढ़-चढ़ कर इस पर काम भी कर रही थी। आज जब इन विपक्षी दलों का वजूद ख़त्म हो रहा है, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनकी हार हो रही है, जनता उन्हें लगातार खारिज कर रही है, इसलिए कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी आंदोलन में कूद पड़ती है। किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक पार्टियां उनके मंच पर न आयें, लेकिन निहित स्वार्थों के कारण ये जबरन उसमें शामिल हो रहे हैं। ये पहला आंदोलन नहीं है जिसका कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी सीएए, शाहीन बाग और कई अन्य अवसरों पर ये अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस एवं उसकी सहयोगी पार्टियां केवल विरोध के लिए विरोध कर रही हैं और ऐसा करते समय वे पूर्व में किये गए अपने कामों को भी भूल जाती हैं।

- **मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में जो पार्टियां शामिल थीं या फिर जिन्होंने समर्थन दिया था, उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी समेत कई राजनीतिक दल थे। उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर अपना समर्थन दिया था, परंतु आज ये सभी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर रही हैं। किसानों का अहित करने में ये सभी पार्टियां बराबर की दोषी हैं**

श्री प्रसाद ने कहा कि आज मैं अकाट्य सबूतों के आधार पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के शर्मनाक चेहरों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान कृषि सुधारों का समर्थन किया था लेकिन आज वही पार्टियां उन सुधारों का विरोध कर किसानों को गुमराह कर रही हैं।

- कांग्रेस ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का वादा किया था। 2019 के

चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने कृषि पर किये गए कांग्रेस के वादे के 11वें पॉइंट में स्पष्ट लिखा है कि Congress will repeal the Agricultural Produce Market Committees Act and make trade in agricultural produce - including exports and inter-state trade - free from all restrictions. कांग्रेस का एक और दोहरा रवैया देखिये कि अंग्रेजी में तो ये 'repeal' की बात करती है लेकिन हिंदी में घोषणापत्र जारी करते समय ये कहती है कि हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। इसी तरह कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में Essential Commodities Act (ECA) को एक नए कानून को लाने की बात कही थी। अब जब मोदी सरकार ने किसानों को सशक्त करने के लिए इस एक्ट में संशोधन किया है तो कांग्रेस इसका विरोध कर किसानों को ही भ्रमित रही है।

- कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एपीएमसी एक्ट को लेकर दिए अपना बयान याद हो या नहीं, लेकिन आम लोगों को पता है कि 27 दिसंबर, 2013 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फलों और सब्जियों को APMC एक्ट से बाहर करने का ऐलान किया था, ताकि किसान अपनी पैदावार जहां चाहें बेच सकें। कांग्रेस ने इसे अपनी सरकार वाले राज्यों में लागू भी किया था।

हम विरोध के नाम पर विरोध करने की नीति और अपना राजनैतिक अस्तित्व को बचाने देश के किसानों को गुमराह करने के कांग्रेस एवं उसकी सहयोगी पार्टियों के साथ-साथ कुछ अन्य विपक्षी दलों के कृत्य की कड़ी भर्त्सना करते हैं। विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि संसद द्वारा पारित किये गए तीनों कृषि सुधार विधेयक किसानों की मजबूती एवं उनकी आय को बढ़ाने के लिए हैं

- यूपीए सरकार में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री शरद पवार ने अगस्त, 2010 और नवंबर 2011 के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बार-बार मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने और स्टेट एपीएमसी एक्ट्स में संशोधन के लिए कहा था और भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्रों के संपूर्ण विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए बेहतर मार्केट की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने 11 अगस्त, 2010 को दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित एवं नवंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को इस बारे में पत्र लिखा था जो मीडिया में उपलब्ध है। उन्होंने निजी तौर पर सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि किसानों की बेहतरी के लिए बिना देरी करे राज्य सरकारें कदम उठाए। 2005 में पत्रकार शेखर गुप्ता को इंटरव्यू देते हुए शरद पवार ने कहा था कि अगर मंडी सुधार नहीं करेंगे तो उन्हें सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा। उन्होंने तो पेनाल्टी लगाने की भी बात कही थी। जब उनसे पूछा गया कि एपीएमसी एक्ट कब तक खत्म होने की उम्मीद है तो शरद पवार ने छः महीने की टाइम लाइन भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि राज्यों को एपीएमसी में संशोधन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए वैकल्पिक साधन सुलभ हो सके और निजी व सहकारी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जा सके।
- कृषि सुधारों के मामले में स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट आई है जिसमें श्री मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं और मैं मानता हूं कि वे समाजवादी पार्टी की नीतियों की आखिरी आवाज हैं। इस रिपोर्ट में भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाय। समाजवादी पार्टी हो या शिव सेना, इन्होंने क़ानून पारित होते समय संसद में सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दी थी।
- एपीएमसी में सुधार को लेकर योजना आयोग ने भी गहन विचार-विमर्श किया था और इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी। योजना आयोग ने 2011 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एपीएमसी सिस्टम में तत्काल सुधारों की जरूरत है और मॉडल एपीएमसी एक्ट में प्राइवेट सेक्टरों की भी भागीदारी को अनुमति दी गई है, ताकि किसानों को अपने हिसाब से अवसर मिले और उन्हें लाभ पहुंचे। योजना आयोग ने इस रिपोर्ट में कहा था कि एपीएमसी में सुधार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए किसानों को बेहतर ग्रामीण ढांचा मुहैया कराए जाने की जरूरत है। साथ ही, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाना चाहिए।
- 2007-2012 के मध्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मनमोहन सरकार ने कानून बनाए थे जिसे उस वक्त आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम और तेलंगाना जैसे राज्यों ने लागू किया था, ताकि किसानों को नए अवसर मिलें और उनकी आय बढ़े। इसमें से कई राज्यों में उस वक्त कांग्रेस सरकार थी।
- यूपीए सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में 2006 में कृषि सुधारों पर एक कमीशन गठित की थी जिसने नियंत्रण मुक्त कृषि बाजार की भी जरूरत बताई थी। यूपीए सरकार ने 2010 में पाटिल कमिटी गठित की थी जिसने 2013 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में नियंत्रण मुक्त कृषि बाजार, कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग,

पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बताई थी।

- मोदी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान ने सरकार पर एपीएमसी में सुधार से हाथ खींचने का आरोप लगाया था, लेकिन जब ये संशोधन हुए हैं तो वे विरोध कर रहे हैं।
- अरविंद केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर, 2020 को कृषि सुधार कानून को दिल्ली में नोटिफाई किया था लेकिन आज विरोध कर रहे हैं।
- पंजाब की कांग्रेस सरकार तो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पेप्सिको जैसे प्राइवेट प्लेयर को मौके दे रही है लेकिन जब हम किसानों के हित में ही इसका कानून बनाते हैं तो कांग्रेस विरोध करने लगती है।

श्री प्रसाद ने कहा कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में जो पार्टियां शामिल थीं या फिर जिन्होंने समर्थन दिया था, उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी समेत कई राजनीतिक दल थे। उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर अपना समर्थन दिया था, परंतु आज ये सभी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर रही हैं। किसानों का अहित करने में ये सभी पार्टियां बराबर की दोषी हैं। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने प्रारंभ से ये कहा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को एंट्री नहीं देंगे, परंतु आज जो हो रहा है, उससे किसान हितों को समर्पित और जीवन भर किसानों की सेवा करने वाले लोगों को भी गहरा धक्का लगा है।

श्री प्रसाद ने कहा कि किसान कुछ निहित स्वार्थों की राजनीति के चंगुल में फंसे हुए हैं। छोटे और मंझोले किसानों को हम उनके फसल और बाजार के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जायेगी और न ही बंधक होगी। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं होगी। देश के जो छोटे-मंझोले किसान समय के अनुसार बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अवसर क्यों न मिले? उन्होंने ई-नाम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब तक ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म पर 1000 मंडियों, 1.68 करोड़ किसानों और 1.51 लाख ट्रेडर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके माध्यम से अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार क़ानूनों के लागू होने के बाद भी 6 खरीफ फसलों और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। नवंबर अंत तक लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के 318 लाख टन धान का प्रोक्योरमेंट किया गया है। इसका लगभग 64% अर्थात् 202 लाख टन धान का प्रोक्योरमेंट केवल पंजाब से किया गया है। यदि हमारा मंडी और एमएसपी ख़त्म करने का इरादा होता तो क्या धान की इतनी बड़ी खरीद होती क्या?

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के प्रति सदैव समर्पित है। केंद्र सरकार किसानों के लिए नये-नये अवसर तलाश कर उन्हें किसानों के लिए उपलब्ध कराना चाहती है ताकि किसान सशक्त बनें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलें।

श्री प्रसाद ने कहा कि हम विरोध के नाम पर विरोध करने की नीति और अपना राजनैतिक अस्तित्व को बचाने देश के किसानों को गुमराह करने के कांग्रेस एवं उसकी सहयोगी पार्टियों के साथ-साथ कुछ अन्य विपक्षी दलों के कृत्य की कड़ी भर्त्सना करते हैं। विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि संसद द्वारा पारित किये गए तीनों कृषि सुधार विधेयक किसानों की मजबूती एवं उनकी आय को बढ़ाने के लिए हैं। सरकार खुले मन के साथ हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। ■

एम. विजयाशांति और पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक भाजपा में शामिल

प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेत्री श्रीमती एम. विजयाशांति नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में 7 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इससे पहले, श्रीमती एम. विजयाशांति ने भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। श्रीमती विजयाशांति मेडक (तेलंगाना) से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी और साल 2009-2014 के बीच इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 40 साल के फिल्मी जीवन में उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है।

इससे पूर्व, टीएमसी के विधायक श्री मिहिर गोस्वामी 27 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। श्री विजयवर्गीय ने कहा, "वह उत्तर बंगाल के कूच बिहार के एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। वह कूच बिहार(दक्षिण) विधानसभा सीट से विधायक हैं।" ■

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में तेजी

नवंबर, 2020 में 62,782 करोड़ रुपये का एफपीआई आया

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश में तेजी बनी हुई है, जबकि पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। इन कठिन परिस्थितियों में भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में तेजी ने भारत के विकास गति को बरकरार रखा है। निवेश में तेजी का सीधा अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर निवेशकों का भरोसा बरकरार है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)

पिछले दो महीने, अक्टूबर और नवंबर में एफपीआई में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसकी एक प्रमुख वजह इक्विटी के जरिए एफपीआई में रिकॉर्ड तेजी आना है जो कि किसी महीने में सबसे ज्यादा एफपीआई प्रवाह था। नवंबर, 2020 को (28 नवंबर तक) भारत में 62,782 करोड़ रुपये का एफपीआई प्रवाह हुआ। इस दौरान कुल निवेश में 60,358 करोड़ रुपये इक्विटी के जरिए एफपीआई आया। जबकि डेट और हाइब्रिड के जरिए 2,424 करोड़ रुपये का एफपीआई भारत में आया है।

गौरतलब है कि इक्विटी कैटेगरी में नवंबर, 2020 के दौरान हुए रिकॉर्ड एफपीआई निवेश के आंकड़ें नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

वैसे तो एफपीआई निवेश बाजार की बदलती परिस्थितियों को सीधे प्रभावित नहीं करता है, लेकिन एफपीआई आंकड़ों से इस कुल निवेश और उसकी निकासी की स्थितियों का भी पता चलता है। अक्टूबर-नवंबर 2020 के दौरान भारत में निकासी से ज्यादा एफपीआई निवेश हुआ है।

इसके अलावा नवंबर के महीने से लेकर आज तक इक्विटी कैटेगरी में निवेश में तेजी बनी हुई है। सबसे ज्यादा एफपीआई प्रवाह का रिकॉर्ड 12 नवंबर को हुआ, उस दिन 11,056 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान भारत में 28,102 अरब डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेश निवेश हुआ है। इसके तहत 23,441 अरब डॉलर यानी 174,793 करोड़ रुपये का एफडीआई इक्विटी के रूप में आया है। दूसरी तिमाही के निवेश के आधार पर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में (सितंबर, 2020 तक) 30,004 अरब डॉलर का एफडीआई आया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 15 फीसदी ज्यादा है।

रुपये के आधार पर देखा जाये तो इस अवधि में इक्विटी के रूप में एफडीआई 224,613 करोड़ रुपये का आया है जो कि बीते वित्त वर्ष की तुलना में 23 फीसदी बढ़ा है। इस दौरान अगस्त का महीना एफडीआई के आधार पर काफी उल्लेखनीय रहा है। इस महीने 17,487 अरब डॉलर का एफडीआई इक्विटी के रूप में आया है। इक्विटी के जरिए एफडीआई और कुल एफडीआई निवेश में पिछले कुछ वर्षों में तेजी बनी हुई है जो कि पिछले छह साल में 2019-20 के दौरान अधिकतम था।

इस तेजी की प्रमुख वजह सरकार द्वारा एफडीआई सुधार, निवेश सुविधाओं में बढ़ोतरी, व्यवसाय करने में सुगमता लाने के लिए उठाए गए कदम हैं। जिसका परिणाम है कि भारत में एफडीआई प्रवाह बढ़ा है।

कुल एफडीआई प्रवाह (मिलियन, अमेरिकी डॉलर में)

वित्त वर्ष	इक्विटी आधारित एफडीआई	कुल एफडीआई
2014-15	29737	45148
2015-16	40001	55559
2016-17	43478	60220
2017-18 (अनंतिम)	44857	60974
2018-19 (अनंतिम)	44366	62001
2019-20 (अनंतिम)	49977	74390

स्रोतः डीपीआईआईटी

बॉन्ड मार्केट

वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 4.43 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किए गए, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 3.54 लाख रुपये के कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किए गए थे। जो कि पिछले साल की तुलना में 25 फीसदी ज्यादा है।

जिस तरह से कॉरपोरेट बॉन्ड में तेजी आई है, उससे साफ है कि कॉरपोरेट अब सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों की जगह बॉन्ड मार्केट पर भरोसा कर रहे हैं। इस कदम से सरकार और कॉरपोरेट के लिए भी पूंजी जुटाने की लागत घटेगी। इसके साथ ही आरबीआई की उदार मौद्रिक नीति से तरलता बढ़ी है। इस वजह से डेट मार्केट में यील्ड भी घटी है। ■

नवंबर, 2020 महीने में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,04, 963 करोड़ रुपये

नवंबर, 2020 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 1.4 प्रतिशत अधिक

नवंबर, 2020 के महीने में कुल 1,04,963 करोड़ रुपये जीएसटी राजस्व एकत्र हुआ, जिसमें से सीजीएसटी 19,189 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,540 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 51,992 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 22,078 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 8,242 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 809 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। नवंबर महीने में 30 नवंबर, 2020 तक दाखिल किए गए जीएसटीआर-3 बी रिर्टन की कुल संख्या 82 लाख है।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी को 22,293 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी को 16,286 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नवंबर, 2020 के महीने में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने सीजीएसटी से 41,482 करोड़ रुपये और एसजीएसटी से 41,826 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया है।

जीएसटी राजस्व में वसूली के हालिया रुझान के अनुरूप नवंबर,

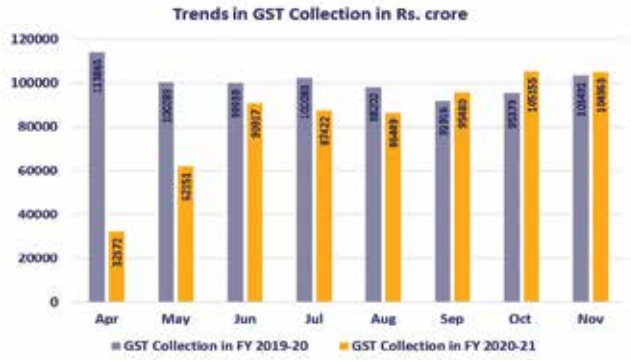

2020 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 1.4 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व माल के आयात से राजस्व 4.9 प्रतिशत अधिक और घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व 0.5 प्रतिशत अधिक हैं। ■

भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ) के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में 2 दिसंबर, 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19.02.2020 की अपनी बैठक में बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी थी। एमओयू का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग को इस प्रकार से बढ़ाना है:

- जनता, उद्योगों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) संगठनों और लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के बीच कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से, कार्यक्रमों और प्रतिभागियों द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से;
- कार्यक्रमों, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, तकनीकी आदान-प्रदान और आउटरीच गतिविधियों में सहयोग से बौद्धिक संपदा के संबंध में परस्पर आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त करना और सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के प्रसार की सुविधा प्रदान करना;
- पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत और औद्योगिक डिजाइन, साथ ही साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, प्रवर्तन और उपयोग के लिए आवेदन के पंजीकरण और परीक्षा के लिए प्रक्रियाओं पर सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान;
- बौद्धिक संपदा में स्वचालन और आधुनिकीकरण परियोजनाओं, नए प्रलेखन और सूचना प्रणालियों के विकास और कार्यान्वयन पर सूचना का आदान-प्रदान और बौद्धिक संपदा कार्यालय सेवाओं के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं;
- पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए सहयोग और पारंपरिक ज्ञान डेटाबेस से संबंधित और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए मौजूदा बौद्धिक संपदा प्रणाली के उपयोग पर जागरूकता बढ़ाने सहित सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान; तथा अन्य सहयोग गतिविधियों के रूप में प्रतिभागियों द्वारा परस्पर निर्णय लिया जा सकता है।

दोनों पक्ष समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए द्विवार्षिक कार्य-योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना शामिल होगी।

समझौता ज्ञापन भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और दोनों देशों को एक-दूसरे के अनुभव से सीखने के अवसर प्रदान करेगा, विशेष रूप से दूसरे देश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में। यह वैश्विक नवाचार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में भारत की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और राष्ट्रीय आईपीआर नीति, 2016 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा। ■

जीएसटी कार्यान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए सभी राज्यों ने चुना विकल्प-1

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 5 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सभी 28 राज्यों और विधान सभा वाले 3 केंद्रशासित प्रदेशों ने जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में गिरावट को पूरा करने के लिए विकल्प-1 पर अमल करने का निर्णय लिया है। एकमात्र शेष राज्य झारखंड ने भी अब विकल्प-1 के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। विधान सभा वाले सभी 3 केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी परिषद के सदस्य हैं और वे विकल्प-1 के पक्ष में निर्णय पहले ही कर चुके हैं।

भारत सरकार ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक विशेष उधारी योजना शुरू की है, जिन्होंने जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए विकल्प-1 के तहत उधारी लेने का विकल्प चुना है। यह योजना 23 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी हो चुकी है और भारत सरकार राज्यों की ओर से पांच किस्तों में 30,000 करोड़ रुपये पहले ही जुटाकर उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रेषित कर चुकी है जिन्होंने विकल्प-1 को चुना है। अब झारखंड राज्य को भी अगले दौर से इस योजना के तहत जुटाई गई रकम में से उधारी मिलना शुरू हो जाएगी। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपये की अगली किस्त 7 दिसंबर, 2020 को जारी की जाएगी।

विकल्प-1 की शर्तों के अनुसार जीएसटी कार्यान्वयन के कारण पैदा होने वाली राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष उधारी योजना की सुविधा के अलावा 17 मई, 2020 को राज्यों को भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत अतिरिक्त 2 प्रतिशत उधारी लेने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, राज्य अंतिम किस्त के तौर पर अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत रकम बिना शर्त उधार लेने के भी हकदार हैं। यह 1.1 लाख करोड़ रुपये की विशेष योजना के अतिरिक्त है। विकल्प-1 चुनने की सूचना मिलने के बाद भारत सरकार ने झारखंड राज्य सरकार को 1,765 करोड़ रुपये (झारखंड के जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत) की अतिरिक्त उधारी आवंटित की है। ■

सेल ने कच्चे इस्पात उत्पादन में 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की

भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने नवंबर, 2020 के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन में 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। नवंबर में इसका कुल उत्पादन 1.417 मिलियन टन रहा। पिछले साल की समान अवधि (सीपीएलवाई) के दौरान 1.328 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था। इसके पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएसपीएस) में नवंबर, 2020 में 1.402 मिलियन टन उत्पादन हुआ। इससे पहले नवंबर, 2019 में यह आंकड़ा 1.303 मिलियन टन था।

इसके अलावा सेल ने बिक्री के मामले में भी अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा है। कंपनी ने नवंबर, 2020 में 1.39 मिलियन टन इस्पात की बिक्री की। चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) के शुरुआती महीनों में कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अप्रैल-नवंबर, 2020 की अवधि में निरंतर सुधार की वजह से संचयी बिक्री में 2.7 फीसदी की वृद्धि हुई। ■

भारत में पिछले 140 दिनों के बाद कोरोना के सक्रिय मामले 4 लाख से नीचे

देश में इस समय कुल रिकवर मरीजों की संख्या 91 लाख से ज्यादा

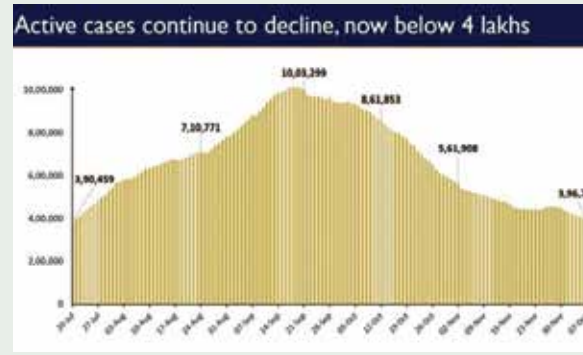

भारत ने 7 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की, क्योंकि देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 4 लाख से कम होकर 3,96,729 रह गए हैं और यह संख्या कुल मामलों का मात्र 4.1 प्रतिशत है। यह पिछले 140 दिनों की अवधि में सबसे कम संख्या है।

कोरोना से ठीक होने वाले नए मरीजों की संख्या नए मामलों की तुलना में काफी ज्यादा देखी गई है और इसकी वजह से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर 94.45 प्रतिशत हो गई है।

देश में इस समय कुल रिकवर मरीजों की संख्या 91,39,901 है और 7 दिसंबर को कोरोना से ठीक हुए मरीजों तथा कोरोना के सक्रिय मामलों का अंतर 87 लाख से अधिक (87,43,172) हो गया है। ■

भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन

4 से 48 सीट तक पहुंची भाजपा

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में चार सीटें हासिल करनेवाली भाजपा ने इस बार 48 सीटों पर विजय प्राप्त की। जीएचएमसी की 150 सीटों में से 99 सीटें हासिल करने वाली सत्तारूढ़ टीआरएस को 55 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। एआईएमआईएम को 44 सीटें मिलीं। वहीं, कांग्रेस को दो सीटों से संतोष करना पड़ा।

ध्यातव्य है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। जीएचएमसी चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान हुए थे, जबकि मतगणना 4 दिसंबर को हुई। इस बार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में मतपत्रों का उपयोग किया गया था। वहीं, कोरोना महामारी के कारण इस बार सिर्फ 35 फीसद ही मतदान हुआ। इन चुनावों में कुल 74 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 38,89,637 पुरुष वोटर और 35,76,941 महिला वोटर शामिल हैं।

भाजपा ने कुशल रणनीति बनाते हुए प्रभावी चुनाव-प्रचार किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, श्रीमती स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बंदी संजय कुमार, भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव-प्रचार किया।

जीएचएमसी चुनाव को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हैदराबाद में रोड शो किया। इस दौरान श्री नड्डा ने लोगों से कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि यहां अब भाजपा के आने की बारी आ गई है। आप ग्रेटर हैदराबाद के विकास के लिए निकाय चुनाव में कमल खिलाने के लिए आतुर हैं। आप भ्रष्टाचार को सिरे से नकार रहे हैं और श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले विकासवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और यहां कमल खिलाकर हैदराबाद को विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने का काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रोड शो के दौरान कहा, "हम तेलंगाना को वंशवाद से लोकतंत्र की ओर ले जाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता और तुष्टिकरण की राजनीति से विकास की ओर ले जाना चाहते हैं।" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मलकजगिरी क्षेत्र में एक रोड शो किया। भाजपा नेताओं के रोड शो में सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ उमड़ी।

चुनाव परिणाम

टीआरएस	भाजपा	एआईएमआईएम
55	48	44
(-44)	(+44)	(0)

150
कुल सीट

पुनर्गणना	कांग्रेस
1	2 (0)

"जीएचएमसी के परिणामों ने वंशवादी, भ्रष्ट और तुष्टिकरण की राजनीति को खारिज कर दिया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय जी और भाजपा तेलंगाना के मेहनती कार्यकर्ताओं को उनके उत्साही प्रयासों के लिए बधाई देता हूं, जिससे बड़ी सफलता प्राप्त हुई। हैदराबाद के लोगों को उनके विश्वास और समर्थन के लिए आभार।
हैदराबाद जीएचएमसी चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत से पता चलता है कि देश के लोग केवल और केवल विकास के एजेंडे का समर्थन करते हैं। यह परिणाम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकास और शासन मॉडल के प्रति लोगों के अप्रतिम समर्थन को दर्शाता है।"

जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की विकास की राजनीति में विश्वास जताने के लिए तेलंगाना के लोगों का आभार। जीएचएमसी में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के लिए श्री जेपी नड्डा जी और श्री बंदी संजय जी को बधाई। मैं भाजपा तेलंगाना के हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं।"

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

"टीआरएस द्वारा काले धन के घनघोर इस्तेमाल और सत्ता के पूर्ण दुरुपयोग के बाद भी जीएचएमसी चुनावों में भाजपा तेलंगाना के पास केवल 8456 वोट कम हैं, जिसके कारण 48 सीट की जीत और मीठी हो जाती है। हम आ चुके हैं। बंदी संजय जी, किशन रेड्डी जी को बधाई।"

बी एल संतोष, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन)

उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में भाजपा ने 6 सीटें जीतीं

हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव परिणामों में भाजपा ने छह सीटों पर जीत हासिल की। 1 दिसंबर को हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं।

मौजूदा चुनाव परिणामों के बाद, राज्य के 100 सदस्यीय उच्च सदन में भाजपा की सीटें 19 से बढ़कर 25 हो गयी है, सपा की 52 से 55 और निर्दलीय की संख्या दो से चार हो गयी है।

इन 11 सीटों में से पांच सीटें स्नातकों के लिए आरक्षित थीं। भाजपा ने उनमें से तीन पर जीत हासिल की - लखनऊ से श्री अवनीश कुमार सिंह, मेरठ से श्री दिनेश कुमार गोयल और आगरा से डॉ मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरुजी' ने जीत हासिल की, इन तीनों उम्मीदवारों ने यह सीटें मौजूदा समाजवादी पार्टी एमएलसी से छीन ली। मेरठ में, श्री गोयल ने चार बार के निर्दलीय एमएलसी हेम सिंह पुंडीर को हराकर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी ने दो सीटों पर जीत हासिल की -श्री मान सिंह यादव ने इलाहाबाद-झांसी मंडल से और आशुतोष सिन्हा वाराणसी से जीते।

छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में से, सत्तारूढ़ भाजपा ने तीन पर जीत

हासिल की - लखनऊ से श्री उमेश द्विवेदी, मेरठ से श्रीशचंद्र शर्मा और बरेली-मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से हरि सिंह ढिल्लों ने जीत हासिल की।

सपा के श्री लाल बिहारी यादव ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से और निर्दलीय श्री आकाश अग्रवाल और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने आगरा और फ़ैज़ाबाद निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः जीत हासिल की। ■

संगठन का आधार

दीनदयाल उपाध्याय

हम लोग संगठन के काम में लगे हुए हैं। संगठन की महत्ता और आवश्यकता समझते हैं। उसके विषय में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यह अलग बात है, जैसा संगठन चाहिए, वैसा दिखता नहीं है। पर कोई ऐसा नहीं मिलेगा, जो कहे, संगठन की आवश्यकता नहीं है। हर एक कहेगा कि हमारा संगठन होना ही चाहिए। उसका मूल कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सा कार्य है, जो वह अकेला कर लेता है, जैसे खाना-पीना। पर इन सब कार्यों को करने के लिए भी दूसरे लोगों की आवश्यकता अनुभव होती है। भोजन के पीछे कितने लोगों के प्रयत्न छिपे हुए हैं। यदि वे सब लोग वह कार्य न करें तो संभवतया यह काम संभव न हो। किसान बोता है, व्यापारी स्थान-स्थान पर पहुंचाता है, कोई साफ़ करता, पीसता और रोटी बनाता-परोसता है, तब कहीं हम खा पाते हैं। फिर हल की आवश्यकता किसान को पड़ती है। वह हल लुहार न बनाए तो काम नहीं चलेगा। व्यापारी फ़सल को ख़रीदता है, पर स्थान-स्थान पर पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी, ट्रक, बैलगाड़ी आदि न हों तो सामान दूसरी जगह पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा हुआ है कि अन्न एक जगह पड़ा है और दूसरी जगह अकाल पड़ा है। सामान पहुंचाया नहीं जा सका। फिर गोदाम में रखवाने के लिए बोरी आदि चाहिए। अतः एक छोटी सी चीज़ के लिए भी एक व्यक्ति को कितने ही लोगों की मदद लेनी पड़ती है। तब कहीं भोजन मिल पाता है।

संगठन का मतलब ही यह है कि सब लोग इस एक बात को ध्यान में रखकर चलें कि हमको और सब लोगों की सहायता के लिए सबके साथ चलना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी ऐसे कार्य हैं, जिनको एक व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता। लाख लोगों का सामान तैयार करने के लिए हज़ारों लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा।

फिर एक व्यक्ति को अकेले आनंद भी नहीं आ सकता। यदि किसी को जेल की काल कोठरी में बाक़ी सब कैदियों से अकेले बंद करके रख दिया जाए, किंतु उसे खाना ठीक समय पर दिया जाए तो भी अकेले बंद रहते-रहते वह इतना ऊब जाता है कि उसे लोगों से मिलने को जी चाहता है। अकेलापन लोगों को खाने को दौड़ता है। अकेले लोगों को डर-सा लगता है, हालांकि बड़े मकान में डर की क्या बात? अच्छा मकान है, ताला बंद है परंतु फिर भी एक साथी मिल जाता है तो उसे समाधान हो जाता है। यह भी भूल जाता है कि यह दूसरा उसका मित्र है या शत्रु। अकेले किसी को गौरव मिल भी जाए। उसका क्या लाभ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नाचने वाले को भी लगता है, चार लोग देखें। विवाह-शादी में व्यक्ति चाहता है, अधिक-से-अधिक लोग आएं। कारण-जितने लोग आते हैं, उनको उतना ही आनंद होता है। ऐसे ही दुःख के अवसरों पर भी। किसी के यहां मृत्यु हो जाती है तो मिलने वाले आते हैं। उनके खिलाने-पिलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। मरने वाला मर गया, व्यवस्था करने में हम भी मर जाएंगे। पर इतना दुःख होते हुए भी व्यक्ति करता है। कारण-उसका सुख बढ़ता है और दुःख घटता है। विद्या के बारे में कहते हैं, जितनी दी जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। सुख के बारे में भी यही बात। जितने लोग बढ़ते जाएंगे, उतना ही सुख बढ़ता जाता है। जितने सहभागी होंगे, दुःख उतना ही बंट जाता है। अतः आदमी अकेले रह ही नहीं सकता। मिलकर ही रहना चाहता है। इसी मिलकर रहने का नाम संगठन है। संगठन में शक्ति है। दो आदमी जब संगठित होते हैं तो एक और एक अर्थात् ग्यारह हो जाते हैं। कोई ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सबका समान स्तर होता है और एक लिख दे तो एक सौ ग्यारह हो जाएगा। जहां ऊपर नीचे का भाव रहता है, वहां सुख बहुत कम बढ़ता है। ताक़त के लिए, आनंद के लिए, भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यहां तक कि जीवन की रक्षा के लिए संगठन आवश्यक है।

पर कैसी संगठन शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए प्रश्न उठता है, किसका संगठन हो? किनके बीच में मेल-मिलाप होना चाहिए? संगठन किनके और उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? उसके आधार पर संगठन करो-ऐसा नारा देते हैं। अमीरों के ख़िलाफ़ ग़रीबों का संगठन होना चाहिए, क्योंकि अमीर हमें सताते हैं। अमीर एक तरफ़, ग़रीब एक तरफ़। कोई कहता है हम एक जाति के हैं। कई समस्याएं आती हैं, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, चमार, लोधा आदि आपस में संगठन कर लें। कोई कहता है, जातियों का कोई उपयोग अब बचा नहीं, केवल विवाह के समय ही उसका उपयोग है। अतः आधुनिक समय के अनुसार एक ही व्यवसाय करनेवाले लोगों का संगठन होना चाहिए। डॉक्टर, वकील, व्यापारी, विद्यार्थी, मास्टर तथा किसान संगठन, क्योंकि इसके कारण समानता हो जाती है। कुछ लोगों की समान रुचियां (Hobbies) होती हैं। गीत गाने वाले, नाचने वाले, लेखक, नाटक करने वालों के भी संगठन होते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं, जो कहते हैं, नहीं, ईश्वर को मानने वालों के आधार पर संगठन होना चाहिए। मसजिद, शिव, यज्ञ हवन करने वाले, भगवान महावीर को मानने वाले और कोई ईसा को मानकर संगठन करने की बात करते हैं। और लोग हैं, जो भाषाओं को महत्त्व देते हैं। भाषा न हो तो अपनी बात प्रकट करना कठिन हो जाए। गूंगा भी भाव प्रकट करता है। पर भाषा के अनुसार संगठन होना चाहिए।

समान राजनीतिक आकांक्षा के आधार पर संगठन बनाने के उददेश्य से भी लोग चलते हैं। इन सबसे ऊपर संपूर्ण मानवमात्र का संगठन करनेवाले भी मिलते हैं। इससे भी ऊपर कहने वाले अभी नहीं मिले, जो कहते हों, संपूर्ण प्राणीमात्र का संगठन होना चाहिए। जानवर भी जीवधारी हैं। अतः बकरी के साथ भी संगठन हो सकने का सोचा जा सकता है।

जब इतनी बहुत सी चीजें आती हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है कि संगठन का आधार क्या हो? संगठन के लिए उसके स्वरूप को सोचना पड़ेगा। आधार प्रथम, कि वह उच्च एवं स्थायी हो तथा दूसरा, वह व्यावहारिक हो।

खेल के मैदान में कबड्डी खेलते हैं। ग्यारह एक पाले में और ग्यारह दूसरे में, उन ग्यारह में संगठन हो जाता है। जो आता है, उसे लौटकर जाने नहीं देना, यह एक विचार होता है। पर यह संगठन कब तक के लिए जब तक खेल है तब तक के लिए। कहीं-कहीं कबड्डी के क्लब होते हैं-वह कुछ अधिक दिन चलते हैं, परंतु वह भी जब कभी मैच होता है। फिर उसमें भी हर बार एक से लोग नहीं होते।

वैसा ही व्यवसाय की दृष्टि से तथा अन्य दृष्टि से संगठन बनते हैं। वे भी अधिक दिन चलते नहीं, फिर उनमें भी समस्याएं बन जाती हैं। अध्यापकों का संगठन बना, उसमें से कोई प्रिंसिपल बन गया तो वह फिर उस संगठन में रहेगा कि नहीं, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल गड़बड़ न करे, इसलिए वह संगठन में था। किंतु अब वह स्वयं ही प्रिंसिपल हो गया, तो वह संगठन उसी के ख़िलाफ़ हो जाएगा।

• राष्ट्र के नाते विचार छोड़कर केवल मानवमात्र का विचार लेकर चले तो वह अव्यावहारिक होगा। सब दृष्टि के विचार करने पर लगेगा कि राष्ट्र के आधार पर ही केवल संगठन हो सकता है

अमीर और ग़रीब के बारे में भी वही बात। आज जो ग़रीब है, कल वह अमीर हो सकता है। जो अमीर है, वह ग़रीब हो सकता है। फिर उसका संगठन के साथ संबंध नहीं। फिर इस अमीर और ग़रीब की रेखा कैसे खींची जाए? एक घेरे में आप खड़े हो जाएं तो आप किसी के दाएं होंगे तो किसी के बाएं होंगे। पूरब भी होंगे तो पश्चिम भी होंगे (उदाहरण एक व्यक्ति चाहता था चपरासी से जिलाधीश हो जाऊं, किंतु ज़िलाधीश को भी डांट सहनी पड़ती है) अर्थात् इस परिधि का अंत नहीं, कोई रेखा नहीं। एक अंग्रेज़ी कविता का भाव कि एक व्यक्ति के पास जाड़े में जूते नहीं थे, किंतु जूते पहनने को इच्छा हुई तो देखा किसी व्यक्ति के पैर भी नहीं हैं तो सोचा हम ही अच्छे हैं। यह सारी बातें ऐसी हैं, जो स्थायी नहीं हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज जो ग़रीब है, स्थायी रूप से ग़रीब रहेगा। क्षितिज को छूने वालों का संगठन, जो सोचते हैं, उन्हें विज्ञान ने बता दिया कि धरती और आकाश कहीं नहीं मिलते। ऐसे लोगों का यदि संगठन बना दिया तो कैसे होगा? यह संगठन एक ग़लत आधार पर होगा।

वैसे ही इन सभी संगठनों में स्थायित्व नहीं है। एक चीज़, स्थायित्व चाहिए और दूसरी वह व्यावहारिक होनी चाहिए। केवल चालीस या पचास लोगों को मिला लेना ही संगठन नहीं, उसका भी एक व्यावहारिक यूनिट होती है। भोजन की व्यवस्था करनेवालों का संगठन, जिसमें केवल रोटी पकाने वालों का या दाल, पानी इत्यादि की व्यवस्था करनेवालों का ही संगठन नहीं, एक पूरी इकाई चाहिए। ठीक उसी प्रकार, जैसे कॉलेज की इमारत बना देने और शिक्षकों को नियुक्त कर देने से ही कॉलेज नहीं चल जाता, उसमें कक्षाओं, प्रयोगशालाओं आदि की व्यवस्था, कॉलेज की सफ़ाई, पुस्तकालय, विद्यार्थियों का कॉलेज में प्रवेश, उनकी शिक्षा, शुल्क, उनका प्राध्यापकों के साथ संबंध और कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके निकलने तक की हर व्यवस्था और कार्य में संगठन की आवश्यकता है। कॉलेज एक इकाई है, किंतु उसमें भी अनेक संगठन बन जाते हैं, जैसे शिक्षकों के, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के।

जीविकोपार्जन के संगठन आख़िर किसी बड़े संगठन के अंग हैं। घड़ी के पुजों के समान सब मिलकर काम करते हैं। परंतु सुई, बाल, कमानी इन सब का मेल न हो तो काम न चले।

यह तो व्यावहारिकता और स्थायित्व के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो लगता है, यह जो संपूर्ण मानव समाज है, हम उसके आधार पर क्यों न खड़े हो जाएं। यह हो तो सकता है, पर आज के समय में यह व्यावहारिक नहीं है। हर एक व्यवहार आपस में एक से नहीं। आज यदि युद्ध छिड़ गया तो मानव का कुछ भाग तो संगठित हो जाएगा किंतु सारा भाग नहीं। किंतु कुछ संगठन हैं, जो मानव के हैं, जैसे यू.एन.ओ.। पर वहां जब बैठते हैं तो किस नाते बैठते हैं? सारा व्यवहार राष्ट्र के नाते होता है। राष्ट्र के नीचे कोई विचार नहीं। ऐसे संगठन तो चल सकते हैं। International Labour Association, World Health Organisation ये सब मानव जाति का विचार करते हैं, पर आधार सबका राष्ट्र है।

राष्ट्र में ही वह स्थायित्व है। राष्ट्र एक व्यावहारिक इकाई है, जैसे एक कोई कारखाना होता है। वह उत्पादन की बात करता है, इसके अलग-अलग भागों से बातें करता हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर, वह भी एक कारखाना है। हमारे बहुत से अंग हैं, सब मिलकर यह शरीर एक व्यावहारिक इकाई है। कभी-कभी हज़ारों हाथ मिलाने की आवश्यकता हो जाती है। गांव में विराट छप्पर उठाने के लिए कोई यदि सोचे लोगों को लाने की क्या ज़रूरत? चालीस हाथ के लिए बीस लोग न लाकर केवल हाथ काटकर ले आए। मतदान के लिए मतदाता को न लाकर केवल उसकी एक अंगुली काटकर ले आएं तो चलेगा? यह सही है केवल अंगुली की ही आवश्यकता है, पर उस अंगुली के पीछे उन लोगों की ताक़त है। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न व्यवहार की दृष्टि से नहीं, व्यावसायिक-मज़दूर के संगठन नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के आधार पर संगठन चाहिए। हां, राष्ट्र के अतिरिक्त जो कोई इकाई होगी, वह छोटी होगी और टूट भी सकती है। यदि उसने किसी को हेय समझा तो चल नहीं पाएगा।

राष्ट्र के नाते विचार छोड़कर केवल मानवमात्र का विचार लेकर चले तो वह अव्यावहारिक होगा। सब दृष्टि के विचार करने पर लगेगा कि राष्ट्र के आधार पर ही केवल संगठन हो सकता है। ■

-मई २०, १९६१, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : प्रयाग

संगठन शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे

(15 अगस्त 1922 - 28 दिसंबर 2003)

श्री कुशाभाऊ ठाकरे नैतिकता, आदर्श व सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ थे। वे निष्काम कर्मयोगी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में उनका योगदान अमूल्य है। वे जीवन-पर्यंत बेदाग रहे। श्री ठाकरे भाजपा के उन नेताओं में से थे जिन्होंने साइकिल चलाकर और चने खाकर पार्टी का काम किया। यही कारण है कि पार्टी में उनका व्यापक प्रभाव था।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म 15 अगस्त, 1922 को मध्य प्रदेश स्थित धार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सुंदर राव श्रीपति राव ठाकरे और माता का नाम श्रीमती शांता भाई सुंदर राव ठाकरे था। इनकी शिक्षा धार और ग्वालियर में हुई थी। 1942 में संघ का प्रचारक बनने के बाद उन्होंने मध्यप्रदेश के कोने-कोने में निष्ठावान स्वयं सेवकों की सेना खड़ी की। वे कुशल संगठनकर्ता थे।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे संघ में काम की शुरुआत उस समय की थी, जब इस संगठन का विस्तार व्यापक नहीं था। सच तो यह है कि किसी विचारधारा और लक्ष्य के प्रति उनके समान निष्ठा बिरले लोगों में देखी जाती है। उनके सार्वजनिक जीवन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। वे प्रारंभ में केवल संघ के काम से जुड़े रहे। जनसंघ (अब भाजपा) की स्थापना के बाद उनका संबंध राजनैतिक गतिविधियों से हुआ। उन्होंने अपने-आपको संगठन तक सीमित रखा और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सदैव कार्य करते रहे।

कार्यकर्ताओं से उनका संबंध अटूट था। 19 अप्रैल, 1996 को भोपाल में उन्होंने कहा था कि हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। जनता ने हम पर चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। जनता को वर्तमान सरकार से बहुत आशा है। ऐसे समय में भाजपा कार्यकर्ताओं का दायित्व बढ़ गया है और हमें अपना दायित्व समझना होगा।

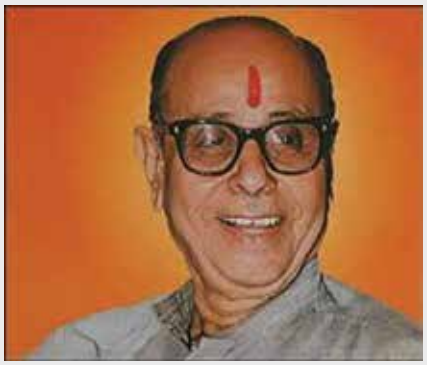

श्री कुशाभाऊ ठाकरे 1956 में मध्य प्रदेश सचिव (संगठन) बने। वे 1967 में भारतीय जन संघ के अखिल भारतीय सचिव बने। आपातकाल के दौरान वे 19 महीने जेल में रहे। 1980 में भाजपा के अखिल भारतीय सचिव बनाए गए। 1986 से 1991 तक वे अखिल भारतीय महासचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे। 1998 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस पद वे 2000 तक रहे। उनका देहान्त 28 दिसंबर, 2003 को हो गया। ■

नहीं रहीं वरिष्ठ भाजपा नेता किरण माहेश्वरी

(29 अक्टूबर 1961 – 29 नवम्बर 2020)

भाजपा नेता और राजसमन्द (राजस्थान) विधायक श्रीमती किरण माहेश्वरी का 29 नवम्बर को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 59 वर्ष की थीं। श्रीमती माहेश्वरी एक लोकप्रिय नेता थीं।

29 अक्टूबर, 1961 को रतलाम में जन्मी श्रीमती किरण माहेश्वरी 24 वर्ष की उम्र में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर लिया। वह एक बार लोकसभा सांसद और राजसमंद विधानसभा सीट से लगातार तीन बार विधायक रहीं।

श्रीमती माहेश्वरी 2004 में उदयपुर-राजसमंद सीट से लोकसभा के लिए चुनी गईं। वह 2008 में पहली बार राजसमंद से विधायक चुनी गईं और उन्होंने राजस्थान की पिछली भाजपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का पद संभाला। उन्होंने 2013 में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इससे पहले वह 2006 में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और कई अन्य नेताओं ने श्रीमती माहेश्वरी के निधन पर शोक व्यक्त किया।

श्रीमती माहेश्वरी के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से पीड़ा हुई। सांसद, विधायक या राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति व गरीबों तथा असहायों के लिए अनेक प्रयास किए। उनके परिवार-जनों के प्रति संवेदना। ओम शांति।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया

कि राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेत्री किरण माहेश्वरी जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र, समाज व संगठन की सेवा के प्रति समर्पित रहा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ■

'सुरक्षित व सस्ते टीके के विकास हेतु दुनिया की नजर भारत की तरफ'

केंद्र सरकार समग्र टीकाकरण रणनीति विकसित कर रही है और विश्व सस्ते और सुरक्षित टीके के विकास के लिए भारत की तरफ देख रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में 4 दिसंबर को आयोजित सर्वदलीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार समग्र टीकाकरण रणनीति विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व सस्ते और सुरक्षित टीके के विकास के लिए भारत की तरफ देख रहा है।

भारत कोविड-19 टीकाकरण के लिए तैयार

प्रधानमंत्री ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन निर्माण के 3 केन्द्रों अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के दौरे में हुए अनुभव साझा करते हुए कहा कि तीन स्वदेशी टीकों समेत कुल 8 संभावित टीके भारत में परीक्षण के अलग-अलग चरण में हैं।

श्री मोदी ने कहा कि संभावना है कि कोविड-19 का टीका आगामी कुछ हफ्तों में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैज्ञानिक इस टीके को स्वीकृति देते हैं भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसे समूहों की पहचान कर रही है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी तथा अधिक जोखिम वाली आम जनता जैसे वृद्ध और बीमारियों से पीड़ित लोग शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि टीकाकरण की व्यवस्था को प्रभावी करने के प्रयास के क्रम में स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के आंकड़ें, टीकों के संग्रहण के लिए ठंडे बक्सों की व्यवस्था, सिरिंज और नीडल की खरीद की तैयारी अगले चरण में हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत की टीका वितरण में विशेषज्ञता और टीकाकरण के एक अनुभवी एवं बड़े नेटवर्क तथा क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह कोविड-19 टीकाकरण में भी हमारी मदद करेगा। राज्य सरकारों के साथ साझेदारी से अतिरिक्त कोल्ड चेन तथा अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी।

गौरतलब है कि टीके के प्रशासन और वितरण के संबंध में कोविड-19 टीका सूचना तंत्र को-विन तैयार किया जा चुका है और जिला तथा राज्य स्तर के पदाधिकारियों और अन्य पक्षों के साथ इसका परीक्षण जारी है।

टीकाकरण अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन

केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की सदस्यता वाले एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, जो कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित अभियान से जुड़ी जिम्मेदारियों को

संभालेगा। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार समग्रता में फैसला करेगा।

भारत ने महामारी के खिलाफ संघर्ष में अदम्य इच्छाशक्ति दिखाई

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारतीयों ने इस महामारी से मुकाबले में अदम्य इच्छाशक्ति प्रदर्शित की। इस समूची लड़ाई में भारतीयों द्वारा दिखाया गया धैर्य, साहस और दृढ़ता अतुलनीय है। उन्होंने आगे कहा कि हमने न सिर्फ भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के प्रयास किए, बल्कि अन्य देशों के नागरिकों की भी हिफाजत में मदद की। भारत ने वैज्ञानिक कार्य प्रणाली अपनाई जिससे भारत में कोविड-19 से संबंधित परीक्षण को तेज़ किया जा सका। इससे न सिर्फ पॉजिटिव दर में कमी आई, बल्कि कोविड-19 से हो रही मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई।

श्री मोदी ने सभी पार्टियों के नेताओं को कोविड-19 लड़ाई में उनके मूल्यवान योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के सहयोग से जन आंदोलन और जन भागीदारी ही भारत में टीकाकरण प्रयासों की सफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से पुनः आग्रह किया कि इस वायरस के खिलाफ जारी बचाव के उपायों में ढिलाई बिल्कुल भी न बरतें।

सर्वदलीय बैठक में जिन पार्टियों ने हिस्सा लिया उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल, शिवसेना, टीआरएस, बीएसपी, एसपी, एआईएडीएमके और बीजेपी शामिल थीं। सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रभावी और तेज टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अपने पूर्ण सहयोग का प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के मुकाबले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और टीके को विकसित करने के प्रयासों के लिए वैज्ञानिक समुदाय तथा टीका उत्पादकों की सराहना की। ■

कोरोना संकट के समय भी देश की विकास यात्रा नहीं थमी: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 30 नवंबर को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में दो फ्लाईओवर पुलों का लोकार्पण किया। पहला फ्लाईओवर ब्रिज सिंधू भवन क्रॉस रोड पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 245 मीटर है और इसके निर्माण पर 35 करोड़ रुपये की लागत आयी है। सानंद जंक्शन पर बनाए गए 240 मीटर लंबे दूसरे फ्लाईओवर ब्रिज पर 36 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं।

इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरखेज-गांधीनगर-चिलोडा नेशनल हाइवे पर ट्रैफ़िक का भार कम करने के लिए जल्द ही सात और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरखेज से चिलोडा के बीच 50 किलोमीटर मार्ग पर निर्बाध ट्रैफ़िक रहेगा और यह देश मे अपनी तरह का एक अनोखा स्ट्रैच होगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने समय से पहले परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार

भी व्यक्त किया।

श्री शाह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हो रहा है। आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में गुजरात देश का नेतृत्व कर रहा है और चहुंमुखी विकास के क्षेत्र में उसने कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात ने गांवों में 24 घंटे बिजली, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास और निजी बंदरगाह जैसे कई विकासात्मक क़दम उठाए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब तक के सबसे बड़े कोरोना संकट के समय भी देश की विकास यात्रा नहीं थमी। श्री शाह ने कहा कि कोरोना संकट से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे गयी है, लेकिन मोदी सरकार के अथक प्रयासों से जल्दी ही भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौटेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के समय को औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति और सामाजिक क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण दूरगामी नीतिगत सुधारों के लिए उपयोग किया। ■

'आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पर ज़ोर'

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 2 दिसंबर को नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 55वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया। इसमें विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक अपने-अपने राज्यों से वर्चुअल तरीक़े से शामिल हुए। यह पहला मौक़ा है जब आसूचना ब्यूरो (इंटेलिजेंस ब्यूरो) ने वर्चुअल रूप में ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजन किया।

पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने 50 पुलिसकर्मियों को भारतीय पुलिस मेडल से सम्मानित किया और मेडल हासिल करने वाले पुलिसकर्मियों को उनकी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी।

अपने उद्घाटन संबोधन में श्री शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को रेखांकित किया और संकट तथा आपदा प्रबंधन में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभाने के लिए पुलिस की सराहना की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पर ज़ोर दिया। नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने पर बल देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने आपातकालीन स्थिति और आपदा से निपटने के लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने निर्देश दिया कि सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य और भारत को एक विकसित तथा सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बाद में वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने पिछले सम्मेलन के कार्य बिंदुओं (Action Points) की समीक्षा की। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के समक्ष आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर एक प्रस्तुति दी गई और लोगों के अनुकूल पहल के साथ समग्र सुरक्षा परिदृश्य को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।

सुरक्षा बलों द्वारा वामपंथी उग्रवाद के मोर्चे पर की गई विभिन्न पहल पर एक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति सुधारने पर विचार-विमर्श हुआ। ■

इन्वेस्ट इंडिया ने 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता

संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है

संयुक्त राष्ट्र (यूएनसीटीएडी) ने इन्वेस्ट इंडिया (नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया) को साल 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया। पुरस्कार समारोह 7 दिसंबर, 2020 को जिनेवा में यूएनसीटीएडी मुख्यालय में हुआ। यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों (आईपीए) की उत्कृष्ट उपलब्धियों और बेहतरीन अभ्यास को प्रतिबिंबित करता है। इसका मूल्यांकन 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के यूएनसीटीएडी द्वारा मूल्यांकन पर आधारित था।

कोविड-19 महामारी ने निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए कई चुनौतियां खड़ी की हैं। उन्हें नियमित निवेश प्रोत्साहन और सुविधा से ध्यान हटाकर संकट प्रबंधन, सरकारी आपातकालीन व आर्थिक राहत उपायों की अधिसूचना, संकट सहायता सेवाओं के प्रावधान और राष्ट्रीय कोविड-19 व्यापार प्रतिक्रिया प्रयासों में योगदान की ओर कर दिया है। यह सब तब किया जा रहा था जब एजेंसियों के कार्यालय बंद थे, सारे कार्य ऑनलाइन हो रहे थे और कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया था।

मार्च, 2020 में यूएनसीटीएडी ने महामारी को देखते हुए आईपीए की प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया। यूएनसीटीएडी ने अप्रैल और जुलाई, 2020 में आईपीए ऑब्जर्वर प्रकाशनों में निवेश संवर्धन एजेंसियों के बेहतरीन कार्यों की सूचना दी। महामारी को लेकर आईपीए की प्रतिक्रिया 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के मूल्यांकन का आधार बनी।

यूएनसीटीएडी ने अपने प्रकाशन में इन्वेस्ट इंडिया की बेहतरीन गतिविधियों जैसे कि बिजनेस इन्युनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लुसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, सोशल मीडिया पर सक्रियता और कोविड से निपटने के लिए गठित समूहों (जैसे कि व्यापार पुनर्निर्माण, स्टैकहोल्डर आउटरीच और सप्लायर आउटरीच) पर प्रकाश डाला। इन्वेस्ट इंडिया ने यूएनसीटीएडी के उच्च-स्तरीय सत्रों में निवेश प्रोत्साहन, सुविधा और प्रतिधारण के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों और कार्य प्रणालियों को साझा किया।

संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यूएनसीटीएडी एक केंद्रीय एजेंसी है, जो आईपीए के प्रदर्शन की निगरानी करती है और वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों की पहचान करती है। जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर यह पुरस्कार जीत चुके हैं।

इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ श्री दीपक बाग्ला ने कहा कि यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री के मेकिंग इंडिया को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में एक वसीयतनामा है। यह उनके विजन आसान जीवन, व्यापार में सहजता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का परिणाम है। ■

प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट इंडिया को दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएनसीटीएडी की ओर से प्रदान किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार को जीतने के लिए इन्वेस्ट इंडिया को बधाई। यह भारत को दुनिया का पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने और व्यापार करने में आसानी की स्थितियों में सुधार लाने की हमारी सरकार के प्रयासों का एक प्रमाण है।

भारत श्रीलंका के विकास का मजबूत साझेदार है: निर्मला सीतारमण

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से 20वें श्रीलंका इकोनॉमिक सम्मेलन (एसएलईएस) में मुख्य भाषण संबोधित किया। इस बार सम्मेलन की थीम 'रोडमैप फॉर टेक ऑफः ड्राइविंग ए पीपुल-सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल' है।

सम्मेलन के दौरान वित्त मंत्री ने भारत द्वारा महामारी के दौरान उठाए गए कदमों के बार में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के आर्थिक विकास के लिए लगातार कदम उठा रहा हैं। इसके लिए जरूरी नीतिगत बदलाव भी किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के 'आत्मनिर्भर अभियान' और 'अपने पर भरोसा रखने वाला (सेल्फ रिलाएंट) श्रीलंका' का विजन एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों देशों के प्रयासों से भारत-श्रीलंका कहीं ज्यादा मजबूत होंगे।

श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और श्रीलंका के नागरिक केंद्रित नीतियों से ही दोनों देशों के लोगों का पूर्ण विकास हो सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका के विकास का मजबूत साझेदार है और आगे भी दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग और निजी क्षेत्र के विकास के लिए एक टिकाऊ और भरोसेमंद नीति होना बेहद जरूरी है। ■

रि-लर्निंग, रि-थिंकिंग, रि-इनोवेटिंग और रि-इंवेंटिंग, कोविड-19 के बाद की व्यवस्था होगी: नरेन्द्र मोदी

सरकार 'रिफॉर्म (सुधार), परफॉर्म (प्रदर्शन), ट्रांसफॉर्म (परिवर्तन)' के सिद्धांत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पैन आईआईटी यूएसएस द्वारा आयोजित आईआईटी-2020 ग्लोबल समिट में मुख्य भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 'रिफॉर्म (सुधार), परफॉर्म (प्रदर्शन), ट्रांसफॉर्म (परिवर्तन)' के सिद्धांत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां कोई भी क्षेत्र सुधारों के दायरे से बाहर नहीं रह गया है। श्री मोदी ने सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए व्यापक सुधारों; जैसे- 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कानूनों में बदलना, दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स दर, उत्पादन के साथ-साथ निर्माण को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के इस चुनौती भरे वक्त में भारत को रिकॉर्ड निवेश मिला है और इस निवेश का बड़ा हिस्सा तकनीकी के क्षेत्र में आया है।

श्री मोदी ने कहा कि आज का हमारा काम कल की दुनिया को आकार देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि री-लर्निंग (नए सिरे से सीखना), री-थिंकिंग (नए सिरे से सोचना), री-इनोवेटिंग (नए सिरे से प्रयोग करना) और रिइंवेंटिंग (नए सिरे से आविष्कार करना) कोविड-19 के बाद की व्यवस्था होगी। लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की एक सीरीज के साथ यह हमारी दुनिया को नए सिरे से नई ऊर्जा से भर देगी।

- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व छात्रों से बहस, चर्चा और तकनीक की उभरती हुई नई दुनिया में समाधानों के जरिए अपना योगदान करने की अपील की**

उन्होंने कहा कि यह 'जीवन की सरलता' सुनिश्चित करेगी और इसके साथ-साथ गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। श्री मोदी ने कहा कि उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के साझेदारी की वजह से महामारी के दौरान बहुत सारे इनोवेशन सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया को नए हालात में ढलने के लिए व्यावहारिक समाधानों की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पैन आईआईटी आंदोलन की सामूहिक शक्ति आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को गति दे सकती है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भारत का ब्रांड एंबेसडर बताया, जिनकी आवाज यह सुनिश्चित करने में बेहद खास है कि दुनिया भारत के दृष्टिकोणों को सही अर्थों में समझ पाए।

वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने पैन आईआईटी आंदोलन से 'गिविंग बैक टू इंडिया' (भारत को वापस देना) को लेकर एक ऊंचा मानदंड स्थापित करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के समय से भारत में हैकथॉन की एक संस्कृति विकसित हो रही है और इन हैकथॉन्स में युवा सोच राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के जबरदस्त समाधान पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को अपना कौशल प्रदर्शित करने और दुनिया के बेहतर व्यवहारों से सीखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप के कई देशों के साथ मिलकर काम कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में शीर्ष गुणवत्ता की प्रतिभा को आपस में जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने काम करने के तरीके में एक आमूल-चूल परिवर्तन का साक्षी बन रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले जब आईआईटी एयरो-स्पेस इंजीनियरों को तैयार करता था, तब उन्हें रोजगार देने के लिए घरेलू स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं था, लेकिन आज अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के साथ मानवता के सामने मौजूद यह अंतिम मोर्चा भारतीय प्रतिभा के लिए खुला है। यही वजह है कि भारत में हर दिन नए स्पेस टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व छात्रों से बहस, चर्चा और तकनीक की उभरती हुई नई दुनिया में समाधानों के जरिए अपना योगदान करने की अपील की। ■

रेल विद्युतीकरण कार्य में जोरदार वृद्धि

उत्तर–पश्चिमी रेलवे के नये विद्युतीकृत दिघावाड़ा–बांदीकुई रेल खंड का उद्घाटन

केन्द्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 29 नवंबर को उत्तर-पश्चिमी रेलवे के नये विद्युतीकृत दिघावाड़ा-बांदीकुई रेल खंड का उद्घाटन किया और दिघावाड़ा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इस नये विद्युतीकृत रेल मार्ग पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जन प्रतिनिधि और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री गोयल ने इस अवसर पर कहा कि गुरु नानक देव जी की जयंती के पूर्व का यह दिन बहुत विशेष है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेलवे तीव्र गति और गुणवत्ता के साथ चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है तथा सभी के सहयोग, टीमवर्क और प्रेरणा से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

रेलवे के कार्यों पर जोर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि राजस्थान में कोटा-मुम्बई लाइन का विद्युतीकरण कार्य 35 वर्ष पूर्व किया गया था और उसके बाद किसी ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। रेलवे में इस पर कार्य करते हुए देशभर में संपूर्ण रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजस्थान के संबंध में उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2009-2014 तक इस क्षेत्र में बिल्कुल भी विद्युतीकरण कार्य नहीं हुआ था जबकि पिछले साढ़े पांच वर्षों में (सितम्बर 2020 तक) 1433 किमी रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हो गया है यानी कि प्रति वर्ष 240 किमी रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया।

श्री गोयल ने कहा कि इन वर्षों के दौरान सोच में परिवर्तन आया है और हमारे काम करने के तरीके में भी बदलाव हुआ है। आज इस रेल मार्ग के विद्युतीकरण के बाद रेवाड़ी से अजमेर के रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है और अब दिल्ली से अजमेर के लिए विद्युतीकृत ट्रेन भी जल्द ही आरंभ होंगी।

उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के संचालन के बाद डीजल ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी जिससे कि प्रदूषण नियंत्रित होगा और बाहर से आयातित ईंधन पर निर्भरता नहीं रहेगी तथा स्वावलम्बी भारत में पैदा होने वाली बिजली से ट्रेनों का संचालन होगा, इससे महत्वपूर्ण राजस्व की भी बचत होगी। इसके अलावा ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी तथा उद्योगों, खेती आधारित कारोबार का विकास होगा और ग्रामीणों व किसानों की तरक्की होगी। किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा उनकी कृषि उपज के परिवहन के लिए किसान रेल का परिचालन किया जा रहा है। सरकार किसानों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री गोयल ने सभी से कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की।

गौरतलब है कि विद्युतीकरण का कार्य केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण (सीओरआरई) प्रयागराज द्वारा किया गया। दिल्ली सराय रोहिल्ला-मदार (अजमेर) के विद्युतीकरण कार्य को सीओआरई द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और रेल विद्युतीकरण परियोजना, जयपुर के सुपुर्द की गई थी। दिल्ली सराय रोहिल्ला-मदार (अजमेर) के विद्युतीकरण के लिए कुल 23418 फाउंडेशन, 26 स्विचिंग स्टेशन, 6 ट्रैक्शन सब-स्टेशन और सात ओएचई डिपो स्थापित किए गए थे। ■

- **विद्युतीकरण का कार्य केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण (सीओरआरई) प्रयागराज द्वारा किया गया है। दिल्ली सराय रोहिल्ला-मदार (अजमेर) के विद्युतीकरण कार्य को सीओआरई द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और रेल विद्युतीकरण परियोजना, जयपुर के सुपुर्द की गई थी। दिल्ली सराय रोहिल्ला-मदार (अजमेर) के विद्युतीकरण के लिए कुल 23418 फाउंडेशन, 26 स्विचिंग स्टेशन, 6 ट्रैक्शन सब-स्टेशन और सात ओएचई डिपो स्थापित किए गए थे**

भारत ने मलेरिया के मामलों को कम करने में हासिल की प्रभावी सफलता: विश्व स्वास्थ्य संगठन

भारत इस बीमारी से प्रभावित अकेला देश है जिसने 2018 के मुकाबले 2019 में मलेरिया के मामलों में 17.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 का कहना है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 दिसंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह रिपोर्ट गणितीय अनुमानों के आधार पर दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित मामलों के बारे में आंकड़े जारी करती है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत इस बीमारी से प्रभावित वह अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामलों में 17.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। भारत का एनुअल पेरासिटिक इंसीडेंस (एपीआई) 2017 के मुकाबले 2018 में 27.6 प्रतिशत था और ये 2019 में 2018 के मुकाबले 18.4 पर आ गया। भारत ने वर्ष 2012 से एपीआई को एक से भी कम पर बरकरार रखा है।

भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बड़ी गिरावट लाने में भी योगदान किया है यह 20 मिलियन से घटकर करीब 6 मिलियन पर आ गई है। साल 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8 प्रतिशत की गिरावट और मौत के मामलों में 73.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

भारत ने साल 2000 (20,31,790 मामले और 932 मौतें) और 2019 (3,38,494 मामले और 77 मौतें) के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34 प्रतिशत की कमी और इस रोग से होने वाली मौतों के मामलों में 92 प्रतिशत की गिरावट लाने में सफलता हासिल की है और इस तरह सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से छठे लक्ष्य (वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 50-75 प्रतिशत की गिरावट लाना) को हासिल कर लिया है।

मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों की संख्या साल 2018 में (4,29,928 मामले और 96 मौतें) के मुकाबले 2019 में (3,38,494 मामले और 77 मौतें) कम होकर क्रमशः 21.27 प्रतिशत और 20 प्रतिशत पर आ गई है। साल 2020 में अक्टूबर महीने तक मलेरिया के कुल 1,57,284 मामले दर्ज हुए हैं जो कि 2019 की इसी अवधि में दर्ज 2,86,091 मामलों की तुलना में 45.02 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

देश में मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 में शुरू हुए थे और 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (एनएफएमई) की शुरुआत के बाद इनमें तेजी आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई, 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017 से 2022) की शुरुआत की जिसमें अगले पांच साल के लिए रणनीति तैयार की गई। ■

जबरन धर्म परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पारित किया अध्यादेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 24 नवंबर, 2020 को 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' पारित कर दिया। 28 नवंबर को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अध्यादेश अमल में आ गया। इस कानून के मुताबिक मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर या धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा और धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

इस कानून में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर एससी-एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।

इसी प्रकार से सामूहिक धर्म परिवर्तन करने या कराने के मामले में भी यह कानून लागू होगा। जिसके तहत ऐसा करने या कराने वाले सामाजिक संगठनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में 3 साल से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन इस सजा को अधिकतम 10 वर्ष की कैद तक बढ़ायी जा सकेगी और ऐसे मामलों में जुर्माने की रकम 50 हजार रुपये से कम नहीं होगी। ■

स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 9 लाख परामर्श का पूरा किया आंकड़ा

नवंबर, 2019 में शुरू ई-संजीवनी आयुष्मान भारत-एचडब्ल्यूसी ने एक साल में 1,83,000 से ज्यादा डॉक्टरी परामर्श दिए

ई-संजीवनी ओपीडी ने 7,16,000 से ज्यादा दर्ज किए डॉक्टरी परामर्श

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन की पहल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में 2 दिसंबर को 9 लाख डॉक्टरी परामर्श का आंकड़ा छू लिया है। ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी प्लेटफार्मों के माध्यम से सबसे ज्यादा परामर्श लेने वाले शीर्ष 10 राज्य हैं- तमिलनाडु (2,90,770), उत्तर प्रदेश (2,44,211), केरल (60,401), मध्य प्रदेश (57,569), गुजरात (52,571), हिमाचल प्रदेश (48,187), आंध्र प्रदेश (37,681), उत्तराखंड (29,146), कर्नाटक (26,906) और महाराष्ट्र (10,903)।

टेलीमेडिसिन वो जगह है जहां दूर बैठे रोगी इंटरनेट के जरिए उपचार करा सकते हैं। ई-संजीवनी पर रियल-टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूर-दूर बैठे रोगी, डॉक्टर और विशेषज्ञ बिना किसी रुकावट के बैठक कर सकते हैं। इन दूरस्थ परामर्शों के अंत में इस प्लेटफॉर्म पर एक इलेक्ट्रॉनिक निदान पत्र भी तैयार किया जाता है जिसके आधार पर दवाइयां ली जा सकती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान दूर-दराज के इलाकों से रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए सशक्त बनाने के मकसद से इन सेवाओं को शुरू किया गया था और अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय की इस सेवा को 28 राज्य शुरू कर चुके हैं। अब ये राज्य टेलीमेडिसिन सेवाओं की दीर्घकालिक सेवाओं के लिए त्वरित रूप से काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-संजीवनी को दो रूपों में लॉन्च किया है- पहला (ई-संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी) जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर के बीच में बातचीत औऱ सलाह की सुविधा है और दूसरे में रोगी की डॉक्टर (ई-संजीवनी ओपीडी) से परामर्श की सुविधा दी गई है। ई-संजीवनी आयुष्मान भारत-एचडब्ल्यूसी को शुरू हुए अब एक साल हो गया है। आंध्र प्रदेश नवंबर, 2019 में इन सेवाओं को शुरू करने वाला पहला राज्य था और तब से विभिन्न राज्यों द्वारा लगभग 240 हब और 5000 से अधिक ऑनलाइन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सुविधा ने 1,83,000 परामर्श पूरे कर लिए हैं।

ई-संजीवनी ओपीडी जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल, 2020 को देश में लॉकडाउन के वक्त हुई, ये दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरी परामर्श लेने का साधन है। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 7,16,000 से अधिक परामर्श दर्ज किए गए हैं। 240 से अधिक ऑनलाइन ओपीडी केंद्रों से ये परामर्श दिए गए हैं। इनमें

सामान्य ओपीडी और विशेष ओपीडी केंद्र शामिल हैं। ई-संजीवनी के दोनों संस्करण उपयोग और क्षमता व कार्यात्मकताओं के मामले में तेजी से विकसित हो रहे हैं।

पंजाब के मोहाली में सी-डैक में ई-संजीवनी की टीम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ राज्य की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मंत्रालय राज्य के साथ इस सेवा को यहां बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसका मकसद राज्य के वंचित वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य भी गरीब और वंचित वर्ग जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उन तक ई-संजीवनी की सेवाएं पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

सी-डैक मोहाली में ई-संजीवनी टीम राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है, ताकि समाज के वंचित वर्ग के लिए भी ई-संजीवनी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की जा सके। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि, गैर-आईटी जानकारों के साथ-साथ उन गरीब रोगियों के लिए भी विभिन्न मॉडलों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं है। ■

नए कृषि सुधारों से किसानों को नए अधिकार और अवसर मिले हैं: नरेन्द्र मोदी

भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवंबर को अपने मासिक 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप काफी विचार-विमर्श के बाद दिया, जिनसे किसानों को 'नए अधिकार और नए अवसर' मिले हैं।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। किसानों की वर्षों से कुछ मांगें थीं और उन्हें पूरा करने के लिए हर राजनीतिक दल ने कभी न कभी वादा किया था, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हुईं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने काफी विचार-विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी मिले हैं।

'मन की बात' में श्री मोदी ने देशवासियों को बताया कि 1913 के आसपास वाराणसी के एक मंदिर से चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा को कनाडा से भारत वापस लाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की तरह ही हमारी विरासत की अनेक अनमोल धरोहरें अंतरराष्ट्रीय गिरोहों का शिकार होती रही हैं। ये गिरोह अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बेचते हैं। अब इन पर सख्ती तो लगायी ही जा रही है, इनकी वापसी के लिए भारत ने अपने प्रयास भी बढ़ायें हैं। ऐसी कोशिशों की वजह से बीते कुछ वर्षों में भारत कई प्रतिमाओं और कलाकृतियों को वापस लाने में सफल रहा है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शिक्षण संस्थानों से नई, नवोन्मेषी पद्धतियां अपनाने और पूर्व छात्रों को जोड़ने के लिहाज से रचनात्मक मंच तैयार करने को कहा।

श्री मोदी ने गुरु नानक जयंती के एक दिन पहले देशवासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए कहा कि दुनियाभर में सिख समुदाय ने गुरु नानक देवजी की प्रेरणा से शुरू की गई लंगर की परंपरा को कोरोना वायरस महामारी के समय में जारी रखकर मानवता की सेवा की है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में गुरु नानक देवजी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से सॉउथ अफ्रीका तक, उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। गुरुग्रन्थ साहिब में कहा गया है– 'सेवक को सेवा बन आई', यानी सेवक का काम, सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आये और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला।

श्री मोदी ने कहा कि गुरु नानक देवजी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंहजी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुरजी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर में ही करतारपुर साहब कॉरिडोर का खुलना बहुत ही ऐतिहासिक रहा। श्री मोदी ने कहा कि इस बात को मैं जीवनभर अपने हृदय में संजोकर रखूंगा।

• यह हम सभी का सौभाग्य है कि हमें श्री दरबार साहिब की सेवा करने का एक और अवसर मिला। विदेश में रहने वाले हमारे सिख भाई-बहनों के लिए अब दरबार साहिब की सेवा के लिए राशि भेजना और आसान हो गया है।

उन्होंने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि हमें श्री दरबार साहिब की सेवा करने का एक और अवसर मिला। विदेश में रहने वाले हमारे सिख भाई-बहनों के लिए अब दरबार साहिब की सेवा के लिए राशि भेजना और आसान हो गया है। इस कदम से विश्व-भर की संगत दरबार साहिब के और करीब आ गई है।

प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही संग्रहालयों और पुस्तकालयों का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश में कई संग्रहालय और पुस्तकालय अपने संग्रह को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में लगभग 10 डिजिटल दीर्घाएं शुरू करने का काम चल रहा है। ■

एडीबी और भारत ने पश्चिम बंगाल में डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन डॉलर के ऋण पर किए हस्ताक्षर

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने 2 दिसंबर को वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाने के लिए 50 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में राजकोषीय बचत में वृद्धि करना, जानकारी आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना और सेवाओं की अदायगी में सुधार करना है।

पश्चिम बंगाल लोक वित्त प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव डॉ. सीएस महापात्रा और एडीबी की ओर से एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनीशी ने हस्ताक्षर किए।

डॉ. महापात्रा ने कहा कि कार्यक्रम में सम्पूर्ण-सरकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है। राज्य की वित्तीय और सूचना प्रणालियों के एकीकरण से सार्वजनिक सेवाओं की अदायगी में सुधार होगा और राजकोषीय बचत में वृद्धि होगी, जिससे राज्य को विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद मिलेगी।

श्री कोनीशी ने कहा कि अंतर-परिचालन सुविधा वाले ई-सरकारी प्लेटफार्मों के समर्थन से कार्यक्रम, पेंशन और भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुव्यवस्थित करेगा, लिंग-आधारित डेटा, कर भुगतान और राजस्व संग्रह की सुविधा प्रदान करेगा।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के तहत एक नए मॉड्यूल की मदद से विकास परियोजनाओं की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकती है। इससे परियोजना का प्रबंधन बेहतर होगा। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में राज्य सरकार के अधिकारियों की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए एक वित्त नीति तथा सार्वजनिक वित्त केंद्र की स्थापना की जायेगी। परिवहन निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जायेगी, जो विश्वसनीय नागरिक-सरकार इंटरफ़ेस की सुविधा प्रदान करेगा।

वर्तमान ऋण एडीबी के 2012 और 2017 के नीतिगत कार्यक्रमों पर आधारित है, जो स्थायी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का समर्थन करता है। इन कार्यक्रमों ने आईएफएमएस को विकसित और लागू करने में मदद की, बेहतर राजस्व प्रशासन के लिए सफल ई-गवर्नेंस प्रणाली स्थापित की, व्यय के युक्तिसंगत बनाने के उपाय किए और सेवा अदायगी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया।

क्षमता निर्माण, आईएफएमएस सुधारों की निगरानी और सुधार क्षेत्रों में सामाजिक और लिंग पहलुओं के एकीकरण को मजबूत करने के लिए ऋण को 3,50,000 डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान द्वारा पूरक किया जाना प्रस्तावित है।

एडीबी एक समृद्ध, समावेशी, सहनशील और सतत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि अत्यधिक गरीबी को मिटाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 1966 में स्थापित एडीबी पर 68 सदस्यों (क्षेत्र के 49) का स्वामित्व है। ■

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर 'रामायण क्रूज सेवा' जल्द ही शुरू की जाएगी

अयोध्या में सरयू नदी पर 'रामायण क्रूज टूर' जल्द ही शुरू किया जाएगा। केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 1 दिसंबर को क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी (घाघरा/राष्ट्रीय जलमार्ग-40) पर पहली लक्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।

क्रूज में वैश्विक स्तर के अनुरूप आवश्यक संरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ लक्जरी और आराम की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। क्रूज के अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट, रामचरितमानस की थीम पर आधारित होंगे। पूरी तरह से वातानुकूलित 80 सीटों वाले क्रूज में घाटों की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए कांच की बड़ी खिड़कियां होंगी। पर्यटकों के आराम के लिए क्रूज रसोई और पेंट्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा। क्रूज में पर्यावरण पर 'शून्य प्रभाव' के लिए जैव शौचालय और हाइब्रिड इंजन प्रणाली है।

पर्यटकों को 1-1.5 घंटे की अवधि के 'रामचरितमानस टूर' पर ले जाया जाएगा। यात्रा के दौरान गोस्वामी तुलसीदास के

रामचरितमानस पर आधारित विशेष रूप से बनाई गई वीडियो फिल्म दिखाई जायेगी, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा होगी। पूरी यात्रा में लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी तय की जायेगी। रामायण के विभिन्न प्रसंगों से प्रेरित कई गतिविधियां और सेल्फी पॉइंट होंगे। यात्रा के बाद सरयू आरती होगी, जिसमें प्रत्येक यात्री सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा। ■

पिछले 6 वर्षों में नगालैंड में 667 किलोमीटर लंबी सड़क को एनएच नेटवर्क में जोड़ा गया: नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 4 दिसंबर को नगालैंड में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार उत्तर पूर्व और नगालैंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान नगालैंड में 667 किलोमीटर लंबी सड़क को एनएच नेटवर्क में जोड़ा गया, जो लगभग 76 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। श्री गडकरी ने कहा कि राज्य में एनएच नेटवर्क को आज 1,547 किमी तक बढ़ा दिया गया है जो 2014 तक 880.68 किलोमीटर ही था। उन्होंने कहा कि नगालैंड में कुछ जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिले राष्ट्रीय राजमार्गों के एक मजबूत नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि 9.90 किलोमीटर/1000 वर्ग किलोमीटर के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राज्य में एनएच नेटवर्क का घनत्व अब 93.30 किलोमीटर/1000 वर्ग किलोमीटर है। श्री गडकरी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या के हिसाब से एनएच नेटवर्क का घनत्व 77.73 किलोमीटर/लाख जनसंख्या है, जबकि राष्ट्रीय औसत 10.80 किलोमीटर/लाख जनसंख्या है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नगालैंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनके सुधार के लिए पिछले 6 वर्षों में 11,711 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले कुल 1063.41 किलोमीटर लंबी सड़क के 55 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें दीमापुर सिटी (नगालैंड का सबसे बड़ा शहर) परियोजना के सुधार के हिस्से के रूप में लगभग 48 किलोमीटर की 3 सड़कें शामिल हैं जिन पर कुल 1,598 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उन्होंने कहा कि 7,955 करोड़ रुपये की लागत वाली 690 किलोमीटर लंबी सड़क का 16 नंबर वाला कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि 966.75 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले 105 किलोमीटर के अन्य सात कार्य अभी निविदा प्रक्रिया के चरण में हैं।

श्री गडकरी ने यह भी संकेत दिया कि 2,127 करोड़ रुपये की लागत वाले 178 किलोमीटर लंबाई के 11 कार्यों को वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़ी लागत के साथ मंजूरी दी जानी है। उन्होंने बताया कि 6,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले 524 किलोमीटर के पांच कार्य डीपीआर चरण में हैं। ■

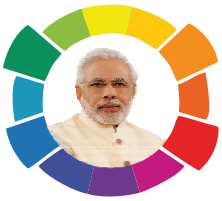

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

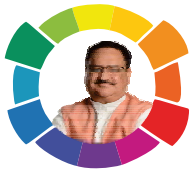

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

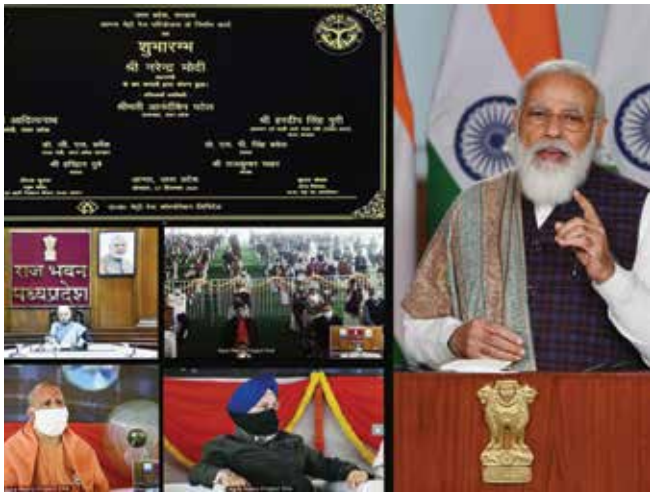

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

काशी में संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड–19 पर आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में देव दीपावली महोत्सव में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में देव दीपावली महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

छायाकार: अजय कुमार सिंह